कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा

शांतिपूर्ण सहयोग और समावेशी विकास के लिए होंगे प्रयास.................. 6
शी जिनपिंग ने पीएलए के उच्च पदों में परिवर्तन किया.......................... 8
श्री शी और श्री मोदी के बीच हुए विचार–विमर्श के प्रमुख बिन्दु........... 9

पं. दीनदयालजी जयंती (25 सितंबर) पर विशेष

एक कर्मयोगी की जीवन यात्रा
– **प्रभात झा**.. 11

लेख

नतीजों की विचित्र व्याख्या
– **हृदयनारायण दीक्षित**.. 15
मजबूत नेतृत्व का असर
– **गुरचरण दास**.. 17
पूर्व प्रधानमंत्री की लापरवाही
– **ए. सूर्यप्रकाश**.. 19
सबका विकास : हमारा आर्थिक दर्शन
– **जयंत सिन्हा**.. 21
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर उभरा भारत
– **डॉ. शिव शक्ति बक्सी**.. 23
हरियाणा में खिलेगा कमल – मिशन 60 प्लस का लक्ष्य
– **संजीव कुमार सिन्हा**.. 26
भारत–चीन सम्बन्ध और जिनपिंग का भारत दौरा
– **विकास आनन्द**.. 28

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

बोध कथा

शांति और साधना

एक सेठ के पास अपार धन-संपत्ति थी, किंतु उसके मन को शांति न थी। एक दिन उसे एक साधु के बारे में पता चला जो लोगों को ऐसी सिद्धि देता है, जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास के पास जाकर बोला, 'महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मन की शांति नहीं है।' साधु ने कहा कि 'जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना।' इससे तुम्हें शांति की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, मगर चुप रहा।

दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने-पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह-तरह के पकवान खाता रहा, सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, 'क्यों, क्या हुआ?' इस बात पर सेठ बोला, 'महाराज, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहां निराशा ही मिली।' इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, 'मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी, पहले दिन जब तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो, तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे।' यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया।

संकलन : सुभाष बुड़ावन वाला

(नवभारत टाइम्स से साभार)

पाथेय

संगठन के कार्यकर्ता न केवल संगठन के सिद्धांतों और विचारों का प्रचार करते हैं, अपितु अपने उन घोषित सिद्धांतों के अनुसार सावधानीपूर्वक जीवन-यापन करते हैं। वे वातावरण निर्माण करते हैं और सिद्धांतों का प्रचार न केवल वाणी द्वारा करते हैं अपितु स्वयं अपने चरित्र और व्यवहार में सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। एक विचार प्रेरित संगठन में संवर्ग को उस संदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना होता है जो वे जनता को प्रदान करना चाहते हैं। सीमेंट-कंकरीट के ढांचे में सीमेंट, रेत और पत्थर मिलकर उतनी ताकत नहीं देते; अत: उनके साथ लोहे की सरिया जमाई जाती हैं जिससे ढांचे में अधिक मजबूती आती है। इसी प्रकार समर्पित कार्यकर्ताओं का योग्य प्रशिक्षित-वर्ग, जो संगठन की प्रगति, स्थायित्व एवं संरक्षण के कार्य में कुशल हो, तैयार करना पड़ता है।

- एकनाथ रानाडे

गर्व से कहो हम भारतीय हैं

विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारतीयों की साख बढ़ी है। अच्छे दिन ही नहीं बल्कि गौरव के दिन लौट रहे हैं। गरीब से लेकर अमीर तक गांव से लेकर शहर तक, झुग्गी से लेकर इमारतों में रहने वालों की चिंता की जा रही है। ईमान की बातें होने लगी हैं। भ्रष्टाचार मौन है। प्रशासन और शासन दिखने लगा है। लावारिस सा भारत अब विश्व में पालने में झूलने लगा है। अरुणोदय से सूर्योदय, सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से रात की चांदनी तक मंत्रालयों के भवन में काम हो रहे हैं।

नयी कार्य संस्कृति जन्म ले रही है। कर्मचारी, कर्मयोगी बन रहे हैं। सरकारी असरकारी हो रहे हैं। नई दिल्ली की स्थित भारत सरकार राज्य सरकारों को नित नये संदेश दे रही है। आपसी विश्वास की ज्योति जलने लगी है। संघीय प्रणाली की साख बढ़ाने का काम हो रहा है। 'सरकार सभी की और सभी सरकार का' भाव स्वत: जग रहा है। भूटान से जापान वाया नेपाल हो या चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो, सभी स्तब्ध हैं और भारत और भारतीय मंत्रमुग्ध हैं। विपक्ष मौन है। अदम्य साहस का परिचय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व रंगमंच पर दे रहे हैं। आशा और अपेक्षा से अधिक सफलता। मंत्रियों में काम करने की होड़ और भारत की समस्याओं को समझने की चाहत।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की वियतनाम यात्रा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूरि-भूरि प्रशंसा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सुन्दर भारत, स्वच्छ भारत, अपना भारत और सबका भारत बनाने की दिशा में भारत सरकार के बढ़ते कदम। साबरमती के संत और गांधी आश्रम की गरिमा में चार चांद लगाने की दिशा में बढ़ते कदम। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' सिर्फ नारा नहीं बल्कि उसे साकार करने की दिशा में पहल प्रारंभ।

विस्तारवाद और अतिक्रमणवाद छोड़कर विकासवाद की ओर बढ़ने का विश्व को आह्वान करने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साहसिक कदम उठाया। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर ''मेक इन इंडिया'' की शुरुआत और 2 अक्तूबर को बापू की जयंती पर भारत स्वच्छता अभियान की शुरुआत अनोखी पहल है। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की ओर भारत को ले जाने की दिशा में जो फैसले हो रहे हैं, वे सराहनीय हैं। जम्मू-कश्मीर में आई आपदा में जो एनडीए सरकार ने भूमिका निभाई और भारत की तीनों सेनाओं ने जो काम किया, वह एक मिशन बना है। जम्मू-कश्मीर की आपदा भारत की आपदा है। सारा देश खड़ा हो गया। आज भारत में इसी भावना की महती आवश्यकता है।

''भाजपा का नेता हूं परन्तु प्रधानमंत्री एक सौ पच्चीस करोड़ व्यक्तियों का हूं'' इसी विचार से नरेन्द्र मोदी काम कर रहे हैं। कांग्रेसी परेशान हैं। उपचुनाव में कुछ सीटें जीतकर सपा या कांग्रेस कुछ सोचे न सोचे पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ?

महाराष्ट्र-हरियाणा जीत गए तो कांग्रेस की कमर टूट जाएगी। भाजपा नेतृत्व को इस दिशा में प्राण-पण से जुटना होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। अगर एनडीए दोनों राज्यों मे जीत गई तो झारखंड और जम्मू कश्मीर का रास्ता सरल हो जाएगा। भारत के ललाट पर एनडीए को परचम फहराने का इससे अच्छा अवसर मिल नहीं सकता।

जनता जाग रही है। जनता का जगना जरूरी है। अवसर मिला है इतिहास गढ़ने का। हम सभी राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को इस महान यज्ञ में जुटना और जुटाना होगा। राष्ट्रीयता जगेगी तो भारतीयता मजबूत होगी। भारतीयता मजबूत होगी तो जातीयता और क्षेत्रीयता की रुग्णता से भारत बाहर जाएगा। ■

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा

शांतिपूर्ण सहयोग और समावेशी विकास के लिए होंगे प्रयास : मोदी

राम प्रसाद त्रिपाठी की एक रिपोर्ट

जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 17 सितंबर 2014 को स्वागत किया तो कई घटनाएं पहली बार हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के बाहर किसी विदेशी प्रमुख का स्वागत किया। देश के राजधानी में अन्तर्राष्ट्रीय करारों पर हस्ताक्षर करने में भी परम्पराओं से हटा गया। श्री मोदी का यह अपवाद इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आगन्तुक दिग्गज को अहमदाबाद का विकास दिखाना चाहा। और इसके अलावा भी, छह दशकों के बाद शी पहले चीनी नेता थे जिनका नागरिक अभिनंदन हुआ, क्योंकि इससे पहले चाऊ-एनलाई का इस प्रकार का अभिनंदन हुआ था। 1962 के बाद चीन के साथ सम्बन्ध अत्यधिक बिगड़ गए थे, जो बाद के वर्षों में सुधरे, परन्तु इस हद तक भी नहीं सुधरे कि कोई भारतीय नेता किसी पड़ोसी देश को सार्वजनिक रूप से दिखा सके, जबकि अन्य देश उपदेश के साथ सतर्कता बरतते रहते हैं।

सीमा तनाव और अन्य मुद्दे जारी रहने पर भी इस जोश को रोक नहीं पाया। दोनों देशों के बीच कैमिस्ट्री बहुत स्पष्ट थी क्योंकि दोनों देश लगातार बात करते रहे और एक दूसरे की कम्पनी में रहकर पूरी तरह अपनापन महसूस करते रहे। श्री मोदी ने श्री शी को सफेद रंग की बिना बांह की जेकेट दी, जिसे पहन कर वे पहले तो श्री नरेन्द्र मोदी के साथ साबरमती नदी के किनारे पर बसे गांधी आश्रम गए और बाद में खूबरसूरत ढंग से सजाए गए श्री मोदी के अत्यंत प्रिय रिवरफ्रंट पर गुजराती संस्कृति और खाने के मजे ने इस मिलन को खुशनुमा बना दिया। चीन के प्रथम दम्पति ने पारम्परिक झूले का भी आनंद लिया और प्रधानमंत्री श्री मोदी उन्हें झूलाते हुए देखते रहे। चीन की प्रथम महिला, जिन्हें चीन में सुपर स्टार सिंगर माना जाता है, भी इस वातावरण को देखकर अत्यंत प्रभावित और आनंदित हुई। श्री शी ने गांधी आश्रम पहुंच कर महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाई और श्री मोदी को 'चरखा' चलाना सिखाया। यह वही चरखा था जिसे गांधी ने 1915 से 1930 तक अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बनाया था।

श्री शी की तीन दिन की भारत यात्रा से अहमदाबाद का गुजराती गौरव परिपूर्ण हो गया। यह ऐसा शहर बन गया जहां पहले किसी देश के प्रमुख शी आए थे। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री के साथ छह घंटे तक रही, जबकि उस दिन मोदी अपना 64वां जन्मदिन मना रहे थे। श्री शी के लिए रिवरफ्रंट पर लक्जरी टैंट लगाया था और वहां उन्होंने स्वादिष्ट शाकाहारी खाना खाया और चीन की

लद्दाख में घुसे फौजियों को वापस भेजो–मोदी

श्री शी के साथ अपनी पहली बैठक में युद्धरत सीमा विवाद पर सर्वप्रथम बोलते हुए कहा कि सीमा पर अमन–चैन बनाए रखने से ही आपसी विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा होने से ही चीन–भारत के सम्बंध पूरी तरह सुलझ सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण समझदारी होगी, जिस पर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और उन्होंने इसे भारत के लिए गम्भीर चिंता का विषय बताया कि चीन इसका अतिक्रमण कर रहा है।

श्री मोदी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूर्ण स्पष्टीकरण करते हुए श्री शी से कहा कि चीन को इस वर्ष लद्दाख में 10 सितम्बर से पूर्व की स्थिति को यथावत करना होगा। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश श्री वांग ई से इस मुद्दे को उठाया। वास्तव में श्री मोदी ने 18 सितम्बर को ही सायं इस बात को कह दिया था और उन्होंने श्री शी को योजनापरांत लद्दाख के चुमार में हुई चीन की नवीनतम अतिक्रमण को सामने रख दिया था।

चीन के राष्ट्रपति अगले दिन श्री मोदी को अपने उत्तर में कहा कि मैंने भारत की चिंता को नोट कर लिया है और लद्दाख की यह घटना सीमा रेखा के रेखांकित न होने के कारण हो सकती है।

सूत्रों का कहना है कि श्री मोदी सीमा मुद्दे को बड़ी सख्ती से उठाते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि चुमार में हुई घटना शिखर पर बैठे चीनी नेताओं की सहमति के बिना नहीं हो सकती हैं। वास्तव में, जहां एक कूटनीतिक प्रयास चल रहे हों उधर आर्मी ने इस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में अपने फौजी भेजे, जो चीनी फौजियों से भी अधिक हो गए। सूत्रों का कहना कि और अधिक सैनिक भी इस क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं जहां नागरिकों ने भी चीनियों को रोकने के लिए मानव दीवार बना ली है, जिसे चीनी अपना क्षेत्र बताते हैं। किन्तु श्री शी ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से द्विपक्षीय सम्बन्धों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। श्री शी ने मीडिया वक्तव्य में कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं स्पष्ट रूप सीमांकन न होने के कारण होती हैं, परन्तु साथ ही यह भी कहा कि दोनों पक्ष न केवल सीमा को प्रभावशाली ढंग से प्रबंध कर सकते हैं, बल्कि शीघ्र ही सीमाविवाद का हल निकाल सकते हैं।

राजग सरकार की प्रथम द्विपक्षीय वार्ता में, जो उच्चतम स्तर पर चीन के साथ हुई, उसके कारण 16 अनुबंधों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए जिसमें चीन अगले पांच वर्षों में 20 बिलियन डालर का निवेश भारत में करेगा। श्री मोदी ने अरूणाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर के निवासियों के लिए चीन की वीजा नीति पर भी चिंता प्रगट की और यह चिंता ट्रांस–बार्डर नदियों के बारे में भी थी, जिसका समाधान न होने से आपसी भरोसा एक निम्न स्तर तक पहुंच जाएगा।

भारत चाहता है कि लद्दाख का गतिरोध तुरंत समाप्त होना चाहिए और मोदी तथा श्री शी ने कहा कि एलएसी स्पष्टीकरण और विवाद का निपटान होने से उनके अमन–चैन के प्रयासों में बड़ी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने श्री शी को कहा कि एलएसी स्पष्टीकरण की रूकी प्रक्रिया को बहाल किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने श्री शी के विचार विमर्श किया जो 75 मिनिट तक चलता रहा। श्री शी से आश्वासन के इलावा, जिसमें कहा गया कि सीमा विवाद शीघ्र सुलझा लिया जाएगा, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण घोषणा पहली बार भारत के लिए की कि चीन के राष्ट्रपति ने शंघाई को–आप्रेशन आर्गेनाइजेशन की सदस्यता का समर्थन किया, जो छह देशों की मध्य एशिया का सुरक्षा ग्रुप है, जिस पर रूस और चीन का प्रभुत्व है।

प्रथम महिला श्रीमती पेंगलियुआन ने भी खाने का आनंद उठाया। श्री शी और उनके शिष्टमंडल का हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वहां राज्यपाल प्रो. ओ.पी. कोहली और मुख्यमंत्री श्रीमती आनन्दी बेन पटेल ने अभिनंदन किया और उसके बाद श्री शी अहमदाबाद के हयात होटल पहुंचे जहां श्री मोदी उनके स्वागत करने का इंतजार कर रहे थे।

नई दिल्ली जाने से पहले उन्होंने और आगे द्विपक्षीय बातचीत कर तीन महत्वपूर्ण अनुबंधों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए, जिससे गुजरात में चीन का निवेश बढ़ेगा। गुजरात वह राज्य है जिसका पिछले अनेक शताब्दियों से व्यापार इतिहास का शानदार रिकार्ड है।

चीन हाई स्पीड रेल कारिडोर में भारत की सहायता करेगा

चीन के राष्ट्रपति श्री शी ने कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर प्रस्तावित एक हाई–स्पीड ट्रेन कारिडोर का निर्माण भारत में करेगा। भारतीय रेलवे चीनी सहयोग से परियोजना के विकास की पहचान करेगी और परियोजना रिपोर्ट तथा इसके वित्त पोषण सम्बन्धी विषय का तैयार करेगी। यह पटरियों को मजबूत करने में मदद करेगी ताकि

यात्री गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 130 किमी प्रति घंटा से बढ़ाकर 160 कि.मी. प्रति घंटा की जा सके।

शुरू-शुरू में चीन के इंजीनियर चेन्नैई-बंगलौर-मैसूर कारिडोर से शुरूआत करेंगे और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 160 कि.मी. प्रति घंटा करेंगे। दिल्ली से आगरा में हाल ही में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के ट्रायल की सफलता को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अन्य आठ कारिडोर पर इसी प्रकार की सेमी हाई स्पीड चलाने की पहचान की है।

दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कार्य योजना के अनुसार चीन के विशेषज्ञ विशिष्ट सेक्शनों का सर्वे और डिजाइन तैयार करेंगे और भारतीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे। चीन रेलवे एर्युअन इंजीनियरिंग ग्रुप हाई-स्पीड रेल कोर्पोरेशन के साथ समन्वय करेगी जो रेल विकास निगम लि. की गौण कम्पनी है। अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल शीघ्र ही चीन जाएगा।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरूणेन्द्र कुमार और चीन के नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक-लू डोंगफू द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध में रेलवे स्टशेनों के पुनर्विकास, भारतीय रेलवे कर्मचारियों के परिवहन सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा भारत में रेलवे विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है।

दोनों पक्षों ने 100 कर्मचारियों (20-20 प्रशिक्षार्थियों के पांच बैच में दो तीन- सप्ताह तक) प्रशिक्षण कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं। प्रशिक्षण 'आन साइट' पर बल दिया गया है, जिसमें आप्रेशन तथा मेनटेंनेंस सुविधा, मानीटिरिंग सिस्टम और ट्रैफिक कंट्रोल पर ध्यान दिया जाएगा। बीजिंग जियाटोंग यूनीवर्सिटी अगले महीने पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी। ■

शी जिनपिंग ने भारत के साथ गतिरोध के बीच पीएलए के उच्च पदों में परिवर्तन किया

22 सितंबर को मिली एक रिपोर्ट के अनुसार समझा जाता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के उच्चतम पदों में फेरबदल कर उनके अपने नजदीकी तीन जनरलों को नियुक्त किया है।

यह घटना एक ऐसे समय में हुई है जब भारतीय सीमा पर गतिरोध छाया रहा, जिससे पीएलए और देश की केन्द्रीय अधिकारियों के बीच संभावित विलगता के

प्रश्न खड़े हो रहे थे।

प्रेजीडेंट ने 21 सितंबर को बुलाई एक बैठक में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित लोगों को भी फांग फंगुई की उपस्थिति में डांटा फटकारा भी।

जिंहुआ न्यूज एजेंसी द्वारा प्रसारित एक सरकारी वक्तव्य में कहा है कि सभी पीएलए बलों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देशों के अनुसार चलना होगा, जिसमें सेंट्रल मिलिटरी कमीशन के चेयरमैन भी शामिल हैं।

भारत के लिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह रहा है कि क्या हाल की शी की भारत यात्रा के दौरान सीमा पर जो घुसपैठ बार-बार की जा रही है, वह राष्ट्रपति की टीम के आधार पर हो रही है या पीएलए उच्च पदों पर बैठे कुछ लोगों के आदेशों पर कोई एक वर्ग ऐसा कर रहा हैं। पिछले दो दिनों की घटनाओं से संकेत मिलता है कि हालांकि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमाण्डर हैं, वे अपने अधिकारों को और मजबूत करने में लगे है।

साउथ चीन मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि प्रेजीडेण्ड शी द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने कई सैन्य अधिकारियों पर निशाना साधा जिससे पीएलए के उच्च पदों और सेंट्रल मिलिटरी कमीशन में हेरफेर किया गया, जिसके वह स्वयं चेयरमैन हैं। 21 सितंबर को सैन्य कमांडरों के साथ शी की बैठक में जारी सरकारी वक्तव्य बताता है कि प्रेजीडेण्ट शी इन बलों ने कई कमांडों से नाखुश हैं। शी ने इस बात पर बल दिया है कि मिलिटरी कमांड में पर्याप्त सुधार और दक्षता की आवश्यकता है। शी ने सभी पीएलए बलों के आप्रेशनल हैडक्वार्टरों को भी सुधारने पर जोर दिया है जिसमें संशोधित प्रोटोकोल भी शामिल हैं। इस वक्तव्य में यह भी कहा है कि बैठक में सभी पीएलए बलों के आपरेशनल हैडक्वार्टरों को धारा में शामिल करने में सूचना प्रौद्योगिकी और अनेक महत्वपूर्ण शिष्टाचारों में परिवर्तन किया है। ■

श्री शी और श्री मोदी के बीच हुए विचार-विमर्श के प्रमुख बिन्दु

- 2015 को चीन में 'विजिट इण्डिया' वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और 2016 को भारत में 'विजिट चीन' वर्ष के रूप में मनाया जाएगा- यह है श्री शी का कहना।
- श्री मोदी का कहना है भारत-चीन शंघाई को-आप्रेशन आर्गेनाइजेशन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन करता है।
- श्री शी ने कहा कि चीन भारत में अगले पांच वर्षों में 20 बिलियन डालर का निवेश करेगा।
- प्रेजीडेंट शी ने कहा कि चीन गुजरात और महाराष्ट्र में दो औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा।
- श्री शी का कहना है कि हममें लाभदायक बातचीत हुई जिसमें आपसी हितों के सभी मुद्दे शामिल रहे।
- श्री शी ने श्री मोदी को चीन आने का निमंत्रण दिया और कहा कि दोनों देश बढ़ते बहु-ध्रुवीय विश्व में महत्वपूर्ण ताकत रखते हैं।
- श्री शी ने कहा कि दोनों देशों को शांतिपूर्ण और समावेशी विकास के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।
- श्री शी का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाईयां छूने की उम्मीद की जा सकती है।
- चीन के राष्ट्रपति ने भारत के बहु विकास और उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की।
- श्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच सम्बन्धों को विस्तार देने का ऐतिहासिक अवसर है।
- श्री मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देश अवसरों और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हैं, अत: मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसे बड़ी सफलता बनाने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे।
- श्री मोदी ने कहा कि स्पष्ट रूप से चीन की वीजा नीति और ट्रांस-बार्डर नदी मुद्दों पर गहन चिंता प्रगट करते हुए श्री शी से इन्हें जल्द सुलझाने को कहा ताकि इन मुद्दों पर आपसी भरोसा बढ़े।
- श्री मोदी का यह भी कहना था कि शांतिपूर्ण और मेल-जोल वाले पड़ोसी हम सबके हित में हैं। हमने क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अच्छी चर्चा की।
- श्री मोदी ने कहा कि हमने विश्व स्तर के अनेक मुद्दों पर सहयोग देने पर सहमत हो गए हैं और हम आतंकवाद और उग्रवाद की चुनौतियों को साझा रूप में सहयोग करेंगे।
- भारतीय प्रधानमंत्री का कहना था कि भारत शांतिपूर्ण और मेलजोल क्षेत्र बनाने में साझा हित देखता है जिसमें शांति, स्थिरता और अफगानिस्तान में समृद्धि भी शामिल है।
- श्री मोदी ने कहा कि हमें सीमा सम्बन्धी प्रश्नों का समाधान करना चाहिए।
- श्री मोदी ने कहा कि सीमा पर जो कुछ हुआ, वह स्पष्ट ही चिंता का विषय है और हमें इस मुद्दे को सुलझाना जरूरी है।
- श्री मोदी ने यह भी कहा कि मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नाथू ला से कैलाश सरोवर के लिए नई सड़क खोलने पर सहमत हो गए।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने प्रेजीडेंट जिनपिंग को बताया कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच व्यापार घाटा बढ़ गया है और उनसे अनुरोध किया कि वे सरल बाजार पहुंच बनाना सुनिश्चित करें और चीन में भारतीय कम्पनियों को निवेश के अवसर प्रदान करें। प्रेजीडेंट जिनपिंग ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा।
- श्री मोदी ने कहा कि हमारे सम्बन्धों और सीमाओं पर शांति रहनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम अपने सम्बन्धों की सच्ची संभावनाएं प्राप्त कर सकेंगे।
- श्री मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रेजीडेंट शी जिनपिंग हमारे सरकार के सत्तारूढ़ होने वाले महीने में भारत आए। अंत में भारत और चीन ने प्रेजीडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में द्विपक्षीय अनुबंध किए।■

2015 को चीन में 'विजिट इंडिया' वर्ष और 2016 को भारत में 'विजिट चीन' वर्ष मनाया जाएगा

अपने दौरे के दूसरे दिन द्विपक्षीय बातचीत के बाद श्री शी ने कहा कि चीन और भारत इस क्षेत्र में वृद्धि और समृद्धि बढ़ाने के लिए दो इंजनों की तरह काम करेंगे। सीमा का रेखांकन न होने के कारण कुछ घटनाएं घटती हैं, परन्तु दोनों देशों के पास ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मैकेनिज्म है। हम दोनों ने एक दूसरे के हितों की चिंता का सम्मान करने का निर्णय लिया है और चीन जल्द से जल्द सीमा मुद्दे का समाधान निकालने के लिए कृतसंकल्प है। इसके अलावा श्री शी ने कहा कि वर्ष 2015 को चीन में 'विजिट भारत' वर्ष मनाया जाएगा और भारत में 'विजिट चीन' वर्ष मनाया जाएगा।■

भारत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकारी यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित दस्तावेज की सूची

1. भारत के विदेश मंत्रालय और चीन जन गणतंत्र के विदेश मंत्रालय के बीच जन गणतंत्र चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रास्ते से भारतीय तीर्थयात्रा (कैलाश मानसरोवर यात्रा) के लिए नया रास्ता खोलने पर सहमति पत्र।
2. भारत गणतंत्र सरकार के रेलवे मंत्रालय तथा जन गणतंत्र चीन सरकार के राष्ट्रीय रेलवे प्रशासन के बीच रेलवे में सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमति पत्र।
3. भारत गणतंत्र सरकार के रेलवे मंत्रालय तथा जन गणतंत्र चीन के राष्ट्रीय रेलवे प्रशासन के बीच रेलवे में सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना।
4. भारत गणतंत्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा जनगणतंत्र चीन सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के बीच पंचवर्षीय व्यापार और आर्थिक विकास योजना।
5. भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह के दसवें सत्र का सहमत कार्यवृत्त।
6. भारत गणतंत्र के सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा जनगणतंत्र चीन के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीवीजन प्रशासन के बीच आडियो-विजुअल सह-उत्पादन पर अनुबंध।
7. भारत गणतंत्र सरकार तथा जन गणतंत्र चीन सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता और सहयोग पर अनुबंध।
8. भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के बीच अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहमति पत्र।
9. भारत गणतंत्र के संस्कृति मंत्रालय तथा जन गणतंत्र चीन के संस्कृति मंत्रालय के बीच सांस्कृतिक संस्थानों के बीच आपसी विनिमय और सहयोग मजबूत करने के लिए सहमति पत्र।
10. भारत गणतंत्र के नेशनल बुक ट्रस्ट तथा जन गणतंत्र चीन के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन स्टेट प्रशासन के बीच सहयोग करने का सहमति पत्र।
11. जन गणतंत्र चीन के चीनी खाद्य तथा ड्रग प्रशासन तथा भारत गणतंत्र के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच कार्य योजना।
12. मुम्बई और शंघाई के बीच सहयोगी नगर सम्बन्धों की स्थापना के लिए अनुबंध।
13. अहमदाबाद और गुआंगझोंग के सहयोगी सम्बन्धों की स्थापना के लिए अनुबंध।
14. गुजरात और गुआंगडोंग के बीच सहयोगी प्रांत/राज्य की स्थापना के लिए अनुबंध।
15. महाराष्ट्र में औद्योगिक पार्कों की स्थापना की सहायता पर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कार्पोरेशन तथा बीकी मोटर कं. लि. के बीच सहमति पत्र।
16. गुजरात में औद्योगिक पार्कों की स्थापना की सहायता के लिए चीन डेवलेपमेंट बैंक कार्पोरेशन तथा इंडेक्स टीवी के बीच सहमति पत्र।

'काला धन वापस लाने को भाजपा प्रतिबद्ध'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हरिद्वार में कहा कि मोदी सरकार बनते ही काले धन को वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

मोदी जी का गंगा अभियान अंजाम तक पहुँचने वाला है। बाबा रामदेव ने जो संघर्ष किया है वो पूरे देश ने देखा है। मैं बाबा के भारतीय भाषाओं के अभियान का बहुत बड़ा समर्थक हूं। बाबा रामदेव ने योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और गुरुकुल परम्परा को आगे बढ़ाया है।

एक संन्यासी परम्पराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आधुनिक से आधुनिक व्यवस्था खड़ी कर सालों तक आगे पहुंचने का इतना बड़ा काम कर सकता है ये मैंने पहली बार देखा है हजारों बच्चो को इस ज्ञान मार्ग पर प्रशस्त होते देख कर दिल में आनंद और संतोष दोनों की अनुभूति होती है। जिस काम के लिए आपने पूरे भारत का भ्रमण किया उसे पूरा करने के लिए भाजपा और सरकार आपके साथ है।

बाबा ने योग को पूरे विश्व में स्वीकृति दिलाई, योग के माध्यम से भारतीय परम्पराओं को स्वीकृति दिलाई। आयुर्वेद दुनिया भर की सेवा का काम कर सकता है। आयुर्वेद के अंदर दुनिया भर के रोगियों के कल्याण की व्यवस्था समाहित है। आयुर्वेद को पुनर्जीवित करके स्वामी जी ने और बाल कृष्ण जी ने एक स्वस्थ दुनिया बनाने का एक अभियान छेड़ा है। ■

पं. दीनदयालजी जयंती (25 सितंबर) पर विशेष

एक कर्मयोगी की जीवन यात्रा

✍ प्रभात झा

बाल्यकाल

दीनदयाल उपाध्याय का बचपन एक सामान्य उत्तर भारतीय निम्न मध्यमवर्गीय सनातनी हिंदू परिवार के वातावरण में बीता। ब्रजभूमि के मथुरा जिले के नंगला चन्द्रभान ग्राम में दीनदयाल उपाध्याय के प्रपितामह विख्यात ज्योतिषी पं. हरिराम उपाध्याय रहा करते थे। श्री झण्डूराम इनके सहोदर लघु भ्राता थे।

पं. हरिराम उपाध्याय के तीन पुत्र थे-भूदेव, रामप्रसाद तथा रामप्यारे। झण्डूरामजी के दो पुत्र थे - शंकरलाल और बंशीलाल।

श्री रामप्रसाद के पुत्र थे श्री भगवती प्रसाद। भगवतीप्रसादजी का विवाह श्रीमती रामप्यारी से हुआ था। वे बड़ी धर्मपरायणा थीं। आश्विन कृष्णा त्रयोदशी संवत् 1973 विक्रमी तदनुसार दिनांक 25 सितंबर, 1916 को भगवती प्रसाद के घर में पुत्रजन्म हुआ। बालक का पूरा नाम दीनदयाल व पुकारने का नाम 'दीना' रखा गया। दो वर्ष बाद रामप्यारीजी की गोद में दूसरा बच्चा आया जिसका नाम शिवदयाल व पुकारने का नाम 'शिबू' रखा गया।

संयुक्त-परिवार-परम्परा

पं. हरिराम के घर में संयुक्त-परिवार-परम्परा अभी तक अबाध चल रही थी। अत: परिवार बड़ा था। दीनदयाल अभी ढाई वर्ष के थे। इनके पिता भगवतीप्रसाद उन दिनों जलेसर में सहायक स्टेशनमास्टर थे। उन्होंने गृहकलह को शांत करने के लिए अपनी चाची तथा विमाता को अपने पास जलेसर बुलवा लिया तथा दीना, शिबू व रामप्यारी को राजस्थान के धनकिया नामक ग्राम में भेज दिया जहां रामप्यारी के पिता चुन्नीलाल शुक्ल स्टेशन मास्टर थे। चुन्नीलाल का पैतृक घर अर्थात् रामप्यारी का मायका तथा दीनदयाल का ननिहाल आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी के पास गुड़-की-मंड़ई नामक ग्राम में था।

ढाई साल की अवस्था में पितृगृह छूटने के बाद दीनदयाल वापस वहां रहने के लिए कभी नहीं लौटे। उनका पालन-पोषण व विकास एक प्रकार से असामान्य स्थिति में हुआ। वे स्थितियां ऐसी भी थी जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व बुझ जाए, लेकिन दीनदयाल उसी परिवेश से ऊर्जा ग्रहण कर अपने व्यक्तित्व का विकास किया। निश्चय ही उनके जीवन पर उनकी बाल्यावस्था के भरपूर संस्कार थे।

जीवन के दु:खद प्रसंग

मृत्यु का दर्शन जीवितजनों में वैराग्य उत्पन्न करता है। दीनदयाल उपाध्याय को बचपन से ही प्रियजनों की मृत्यु का घनीभूत अहसास हुआ। ढाई साल की अवस्था में दीनदयाल अपने नाना के पास आए ही थे कि कुछ ही दिनों में समाचार आया कि उनके पिता भगवतीप्रसाद का देहांत हो गया है। दीनदयाल पितृहीन हो गए व रामप्यारी विधवा हो गई। दीनदयाल की शिशु आंखों ने अपनी विधवा मां की गोद व आंसुओं का तथा दामादविहीन नाना के बेबस व उदास चेहरे का टुकुर-टुकुर अबोध व संवेदनहीन अनुभव ग्रहण किया होगा। पितृहीन शिशु दीनदयाल मां की गोद में बाल्यावस्था को प्राप्त हुए। पर विधवा, शोकाकुल व चिंताकुल रामप्यारी पीड़ा व अपोषण की शिकार होकर क्षयग्रस्त हो गई। उन दिनों क्षयरोग का अर्थ था निश्चित मृत्यु। अभी दीनदयाल सात

वर्ष के तथा शिवदयाल पांच वर्ष के ही हुए थे कि दोनों बच्चों को नाना की गोद में छोड़कर रामप्यारी वास्तव में राम को प्यारी हो गई। दीनदयाल पिता व माता दोनों की स्नेह छाया से वंचित हो गए।

मां के देहांत के दो ही वर्ष हुए थे कि वृद्ध व स्नेही पालक, जो अपनी बेटी की अमानत को पाल रहे थे, नाना चुन्नीलाल भी स्वर्ग सिधार गए। यह 1926 का सितंबर माह था। दीनदयाल अपनी आयु के दसवें वर्ष में थे। माता-पिता व नाना के वात्सल्य से वंचित होकर वे अपने मामा के आश्रय में पलने लगे। मामी नितांत उदार, स्नेहिल व मातृवत् थीं, पर दीनदयाल बहुत गंभीर रहते थे। दस वर्ष का दीनदयाल अपने छोटे भाई शिवदयाल की भी चिंता करता था, उसे स्नेह भी देता था।

दीनदयाल सातवीं की पढ़ाई राजस्थान के कोटा नगर में कर रहे थे। यह सन् 1931 था। उन्हें कोटा से राजगढ़ (जिला अलवर) आना पड़ा, क्योंकि उनकी मामीजी का देहांत हो गया था। अपने पालकों की मृत्यु को निहारते दीनदयाल का यह पंद्रहवां वर्ष था।

इसी छोटी आयु में दीनदयाल अपने सहोदर लघु भ्राता शिवदयाल के पालक भी थे। विधाता की प्रताड़नाओं ने इनका परस्पर स्नेह अधिक संवेदनशील व स्निग्ध कर दिया था। अभी तक दीनदयाल ने अपने पालकों की मृत्यु का ही अनुभव किया था। शायद नियति इस बालक को मृत्यु का सर्वागत: दर्शन करवाने पर तुली थी। जब दीनदयाल नवीं कक्षा में पढ़ रहे थे और अठारहवें वर्ष में थे तब छोटा भाई शिवदयाल रोगग्रस्त हो गया। उसे मोतीझरा हो गया था। दीनदयाल ने अपने छोटे भाई को बचाने की बहुत कोशिश की। सब प्रकार के उपचार करवाए। पर 19 नवंबर, 1934 को शिवदयाल अपने बड़े भाई दीनदयाल को अकेला छोड़कर संसार से विदा हो गया।

अभी भी दीनदयाल पर एक झुर्रियों भरा स्नेहिल आशीर्वाद का हाथ था। वृद्धा नानी दीनदयाल को बहुत प्यार करती थी। हालांकि अपनी पढ़ाई व अन्य पारिवारिक कारणों से वे नानी के पास अधिक न रह सके थे तो भी नानी-दुहिते में अनन्य स्नेह था। यह 1935 का वर्ष था। दीनदयाल ने दसवीं पास की थी। वे उन्नीस साल के हो गए थे। इसी वर्ष जाड़े के दिनों में नानी बीमार हुई और चल बसीं।

पिता, माता, नाना, मामी, लघु भ्राता और अब नानी की मृत्यु ने दीनदयाल को अनुभवसिद्ध किया। उनकी चेतना मौत के प्रहारों से कुम्हलाई तो नहीं, पर युवक दीनदयाल एक सतेज उदासी का धनी बनता जा रहा था। दीनदयाल की एक छोटी ममेरी बहन थी। बहन-भाई के स्नेह-स्निग्ध रिश्ते की सभी तरलताएं इन दोनों के मध्य पूरे तौर पर सुविकसित हुई थी। दीनदयाल आगरा में एम.ए. (अंग्रेजी) की पढ़ाई कर रहे थे। बहन रामादेवी बहुत बीमार हो गई थी। दीनदयाल ने अपनी पढ़ाई छोड़कर रामादेवी की सेवा तथा उपचार के सब साधन जुटाए। पर नियति को यही मंजूर था कि अपनी बहन की मौत का साक्षात्कार भी दीनदयाल को होना चाहिए। बचाने की सब कोशिशों के बावजूद रामादेवी के प्राणपखेरू उड़ गए। यह सन् 1940 था। दीनदयाल चौबीस वर्ष के हो गए थे।

मृत्यु ने उनके शिशु, बाल, किशोर व युवा मन पर निरंतर आघात किए। न मालूम उनके चिरप्रशंसित वैरागी जीवन में नियति के इस तथाकथित क्रूर निदर्शन का कितना हाथ था।

सतत प्रवासी

दीनदयाल अक्षरश: अनिकेत थे। शिशु अवस्था के केवल ढाई वर्ष वे अपने पिता के घर रहे। उसके बाद उनका प्रवासी जीवन प्रारंभ हो गया। वे कभी लौटकर रहने के लिए अपने घर नहीं आए। पारिवारिक कारणों से उन्हें अपने नाना चुन्नीलाल के साथ रहने के लिए धनकिया राजस्थान जाना पड़ा। चुन्नीलाल अपने दो पुत्रों नत्थीलाल व हरिनारायण तथा बाद में दामाद भगवतीप्रसाद (दीनदयाल जी के पिताजी) की मृत्यु से बहुत आहत हुए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी तथा वे अपने घर गुड़-की-मँड़ई आ गए। दीनदयाल के नौ वर्ष के होने पर भी उनके अध्ययन की कोई व्यवस्था न थी। अत: वे अपने मामा राधारमण, जो गंगापुर में सहायक स्टेशन मास्टर थे, के पास आ गए। यहां वे चार वर्ष रहे। गंगापुर में उस समय कक्षा चार से आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। अत: 12 जून 1929 को कोटा के एक स्कूल में उनका प्रवेश हुआ। वे वहां 'सेल्फ सपोर्टिंग हाऊस' में रहते थे। तीन साल वहीं रहे। तत्पश्चात् उन्हें राजगढ (जिला अलवर) आना पड़ा। मामा राधारमण के चचेरे भाई नारायण शुक्ल का स्थानांतरण सीकर हो गया। एक साल सीकर में रहकर दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की। वहां से उच्चशिक्षा के लिए पिलानी गए और दो वर्ष रहकर इंटरमीडिएट किया। यह सन् 1936 था। इसी वर्ष बी.ए. की पढ़ाई के लिए कानपुर गए। यहां दो वर्ष रहकर एम.ए. की पढ़ाई के लिए आगरा गए। यहां राजामंडी में किराए के मकान में रहे। दो वर्ष यहां रहकर 1941 में 25 वर्ष की अवस्था में बी.टी. करने के लिए प्रयाग चले गए। इसके साथ ही उनका

प्रवेश सार्वजनिक जीवन में हुआ और वे अखंड प्रवासी हो गए।

25 वर्ष की अवस्था तक दीनदयाल उपाध्याय राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कम-से-कम ग्यारह स्थानों पर कुछ-कुछ समय रहे। अपना घर, सुविधा व स्थायित्व का जीवन शायद लोगों में मोह उत्पन्न करता है। दीनदयाल का बचपन कुछ यों बीता कि ऐसे किसी मोहजाल की कोई संभावना न थी। सार्वजनिक जीवन में आकर आजीवन बेघर व घुमंतू रहने में प्रारंभिक काल का यह अनिकेती जीवन निश्चय ही उनकी मनसंरचना में सहायक हुआ होगा।

नये-नये स्थान, नये-नये अपरिचित लोगों से मिलना, उनमें पारिवारिकता उत्पन्न करना उन्होंने बचपन की इस अनिकेत अवस्था में ही सीखा होगा, शायद!

मेधावी छात्र जीवन

स्थितियां जिस प्रकार की रहीं तद्नुसार नौ वर्ष की अवस्था तक उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। 1925 में गंगापुर में अपने मामा राधारमण के यहां आने पर उनकी शिक्षा प्रारंभ हो सकी। घर में कोई अन्य विद्यार्थी नहीं था। पढ़ाई का वातावरण नहीं था। गृहदशा पारिवारिक आपदाओं के कारण बहुत क्लांत व तनावभरी थी। सुविधाएं कुछ न थीं। दीनदयाल दूसरी कक्षा के छात्र थे। उनके मामा राधारमण बहुत बीमार पड़ गए। दीनदयाल मामा की सेवा के लिए उनके उपचारार्थ उनके साथ आगरा गए। परीक्षा के कुछ ही दिन पूर्व राधारमण वापस गंगापुर आए। दीनदयाल ने परीक्षा दी। वे कक्षा में प्रथम आए। मामा की सेवा करते हुए ही उन्होंने तीसरी व चौथी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी काल में उनके मेधावी विद्यार्थी होने का परिवार व विद्यालय के लोगों को अहसास हुआ।

कक्षा 5 से 7 की पढ़ाई कोटा में कर उन्होंने 8वीं कक्षा के लिए राजगढ़ में प्रवेश लिया। अंकगणित में उनकी अद्भुत क्षमता का परिचय मिला। जब वे नवीं में थे तो कहते हैं कि दसवीं के विद्यार्थी भी उनसे गणित के सवाल हल करवाया करते थे। लेकिन अगले ही वर्ष उन्हें अपने मामाजी के स्थानांतरण के कारण सीकर जाना पड़ा। उन्होंने दसवीं की परीक्षा कल्याण हाई स्कूल सीकर से दी। वे न केवल प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए वरन् समस्त बोर्ड की परीक्षा में वे सर्वप्रथम रहे। सीकर के तत्कालीन महाराजा कल्याण सिंह ने उनहें तद्निमित्त स्वर्ण पदक प्रदान किया, 10 रुपए माहवार छात्रवृत्ति व पुस्तकों आदि के लिए 250 रुपए की राशि पारितोषिक के रूप में दी।

उन दिनों पिलानी उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। दीनदयाल इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 1935 में पिलानी चले गए। 1937 में इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में बैठे और न केवल समस्त बोर्ड में सर्वप्रथम रहे वरन् सब विषयों में विशेष योग्यता के अंक प्राप्त किए। बिरला कॉलेज का यह प्रथम छात्र था जिसने इतने सम्मानजनक अंकों से परीक्षा पास की थी। सीकर महाराजा के समान ही घनश्यामदास बिड़ला ने एक स्वर्णपदक, 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों आदि के खर्च के लिए 250 रूपए प्रदान किए।

सन् 1939 में सनातन धर्म कॉलेज, कानुपर के प्रथम श्रेणी में बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. करने के लिए सैंट जॉन्स कॉलेज में प्रवेश लिया। एम.ए. प्रथम वर्ष में उन्हें प्रथम श्रेणी के अंक मिले। बहन की बीमारी के कारण एम.ए. उत्तरार्द्ध की वे परीक्षा न दे सके। मामाजी के बहुत आग्रह पर वे प्रशासनिक परीक्षा में बैठे। उत्तीर्ण हुए। साक्षात्कार में भी वे चुन लिए गए। पर, उन्हें प्रशासनिक नौकरी में रूचि न थी। अत: बी.टी. करने के लिए प्रयाग चले गए। इसके साथ ही उनका प्रवेश सार्वजनिक जीवन में हुआ और वे अखंड प्रवासी हो गए।

निर्भीक एवं सेवाभावी

बाल्यावस्था में जब दीनदयाल केवल सात-आठ वर्ष के थे, एक बार उनके घर पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। एक डाकू ने उनकी मामी को धकेलते हुए तथा दीनदयाल को गिराकर उनकी छाती पर पांव रखकर घर के आभूषण मांगे। दीनदयाल ने डाकू के पांव के नीचे दबे-दबे ही कहा, 'हमने सुना था कि डाकू गरीबों की रक्षा के लिए अमीरों का धन लूटते हैं, किंतु तुम तो मुझ गरीब को भी मार रहे हो।' डाकू सरदार पर अबोध बालक की निर्भयता का असर हुआ। वह गिरोह लेकर वहां से चला गया।

इसी प्रकार 1917 में ममेरी बहन रामा के बीमार होने पर उसकी सेवा के लिए न केवल अपनी एम.ए. की पढ़ाई छोड़ दी वरन् जब डॉक्टर व वैद्यों के उपचार से कोई लाभ न हुआ तो स्वयं अध्ययन कर उसको निसर्गोपचार दिया पर वे उसे भी बचा न सके।

राजगढ़ व सीकर में उनकी अध्ययन-क्षमता की धाक तो जम ही गई थी, लेकिन दीनदयाल में इस कारण अहम नहीं वरन् कमजोर छात्रों के प्रति करूणा का भाव उत्पन्न हुआ। पिलानी में कमजोर छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जीरो एसोसिएशन का निर्माण किया जिसमें कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था थी।

स्थितियां ऐसी थीं ही नहीं कि

दीनदयाल के उपद्रवों को कोई सहता। तो भी बालसुलभ चांचल्य तो उनमें था ही। लेकिन एक बार यदि किसी ने उनको टोक दिया तो फिर वे किसी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देते थे। उनके ममेरे भाई व उनकी मामी अभी भी उनके इस स्वभाव को याद करते हैं। स्वाभाविक है, जिस प्रकार की स्थितियां थीं उसमें उनका चांचल्य उपद्रवकारी बने, इसकी कोई संभावना न थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क

दीनदयाल उपाध्याय जब 1937 में बी.ए. की पढ़ाई के लिए कानुपर गए तब अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे के माध्यम से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। वहीं उनकी भेंट संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार से हुई। श्री बाबासाहब आपटे व दादाराव परमार्थ इनके छात्रावास में ही ठहरते थे। इनकी दीनदयाल से बहुत बातें होती थी। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जब कानुपर आए तो दीनदयाल जी उन्हें शाखा आमंत्रित कर 'बौद्धिक वर्ग' करवाया। कानुपर में सुंदरसिंह भंडारी भी उनके सहपाठी थे। कानपुर के इस विद्यार्थी जीवन से ही पं. दीनदयाल उपाध्याय का सार्वजनिक जीवन प्रांरभ हो जाता है।

1937 के बाद 1941 तक वे छात्र रहे। 1941 में प्रयाग से बी.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की, गृहस्थी भी नहीं बसाई। कानुपर, आगरा व प्रयाग में अध्ययन के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर मे ग्रीष्मावकाश में 40 दिन तक चलने वाला 'संघ शिक्षा वर्ग' का प्रशिक्षण प्रथम वर्ष 1939 में द्वितीय वर्ष 1942 में प्राप्त किया। संघ के शारीरिक कार्यक्रमों को दीनदयाल उपाध्याय बहुत ठीक प्रकार नहीं कर पाते थे, लेकिन बौद्धिक परीक्षा में वे प्रथम आए। इस संदर्भ में श्री बाबासाहब आपटे लिखते हैं:

'पं. दीनदयाल जी ने उत्तर पुस्तिका में कई हिस्से पद्यबद्ध लिखे थे, किंतु वह केवल तुकबंदी नहीं थी अथवा केवल कल्पना का विचार भी नहीं था। गद्य के स्थान पर पद्य का माध्यम अपनाया गया था। विवेचन नपेतुले शब्दों में था और वर्णशुद्ध था। मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका।'

अपनी पढ़ाई पूर्ण करने तथा संघ का द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेकवक संघ के प्रचारक बन गए। वे आजीवन संघ के प्रचारक ही रहे। संघ के माध्यम से ही वे राजनीति में गए, भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने, अध्यक्ष रहे तथा एक संपूर्ण राजनीतिक विचार के प्रणेता बने।

भारतीय सार्वजनिक किंवा राजनीतिक क्षेत्र से पं. दीनदयाल का संपर्क 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ही हुआ। तब श्री उपाध्याय 21 वर्ष के नवयुवा थे। तत्कालीन भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों व कांग्रेस के प्रयत्नों के साथ कभी उनका संपर्क नहीं हुआ। संघ के स्वयंसेवक के नाते ही दीनदयालजी ने इन आंदोलनों को देखा। उन्होंने संघधारा को ही अपनी जीवनधारा बनाना स्वीकार किया।

संघप्रचारक एवं दृष्टि पथ

1937 से 1941 तक तो दीनदयाल उपाध्याय छात्र ही थे। वे अध्ययन करते हुए परिश्रमपूर्वक संघ कार्य करते थे। दादाराव परमार्थ, बाबासाहब आपटे एवं भाऊराव देवरस के संपर्क ने उन्हें अपना जीवन संघ कार्य के लिए समर्पित करने को उत्प्रेरित किया। अपना छात्रजीवन पूर्ण करने के बाद उन्होंने 1942 में संघ के प्रचारक के रूप में अपने आपको समर्पित कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय का प्रत्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकाल 1937 से 1951 तक, सामान्यत: चौदह वर्ष रहा। 1937 से 1947, यह दस वर्ष का काल आजादी के आंदोलन का काल था। 1948 से 1951, भारतीय जनसंघ की स्थापना के पूर्व की प्रमुख घटनाओं का काल था। आजादी एवं विभाजन का आगमन, महात्मा गांधी की हत्या, संघ पर प्रतिबंध, संघ द्वारा सत्याग्रह और प्रतिबंध से मुक्ति, संवधिान-निर्माण व भारतीय गणतंत्र की स्थापना, देशी राज्यों का एकीकरण व नवीन राजनीतिक दलों का निर्माण - इस दौरान दीनदयाल की भूमिका संघ के स्वयंसेवकों एवं प्रचारक की रही। हालांकि वर्ष 1952 में वे जनसंघ में शामिल हुए और अ.भा. महामंत्री नियुक्त किए गए, इस पद पर वे 1967 में पार्टी अध्यक्ष बनने तक प्रतिष्ठित रहे।

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का दायित्व संभाला और इस श्रम-साध्य कार्य में अद्‌भुत सफलता प्राप्त की। अपने अथक परिश्रम से उन्होंने भारतीय जनसंघ को विशिष्ट राजनीतिक दल बनाने में अहम भूमिका बनाई।

दीनदयालजी ने 'पांचजन्य' साप्ताहिक तथा लखनऊ से 'स्वदेश' (दैनिक) का संपादन किया। उन्होंने हिन्दी में एक उपन्यास 'चन्द्रगुप्त मौर्य' लिखा और बाद में हिन्दी में ही 'शंकराचार्य' जीवनी लिखी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डा. हेडगेवार की मराठी जीवनी का अनुवाद किया।

11 फरवरी 1968 को त्रासद परिस्थितियों में उनकी मृत्यु से देश को अपार क्षति हुई, जो अपूरणीय थी। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

नतीजों की विचित्र व्याख्या

✍ हृदयनारायण दीक्षित

संसार कार्य कारण की शृंखला है। यहां हरेक घटना का कारण होता है। कारण भी अकारण नहीं होता। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार ही कारण की व्याख्या की जानी चाहिए। देश में लोकसभा व विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसके भी कारण थे। इन उपचुनावों के मिले-जुले नतीजे आए। इसके भी ठोस कारण हैं। जनतंत्र में मतदाता सम्राट होते हैं। लोकसभा चुनावों में उनके सामने भारत एक अखंड इकाई होता है। वे देश का विचार करते हैं। दलों के कामकाज देखते हैं, तद्नुसार वोट देते हैं। विधानसभा उपचुनावों में केवल निर्वाचन क्षेत्र ही विचारणीय मुद्दा होता है। उपचुनाव के नतीजों से केंद्र या राज्य की सरकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो मतदाता स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वोट देते हैं, लेकिन राजनीतिक विवेचकों और भाजपा विरोधी दलों ने चुनाव नतीजों को भाजपा प्रभाव का खात्मा बताया है। उन्होंने स्थानीयता के प्रभाव को जानबूझकर नजरंदाज किया है। उनकी मानें तो चुनाव परिणाम मोदी सरकार के खिलाफ हैं और केंद्र सरकार अल्पमत में हो गई है। ऐसी व्याख्याएं हद दर्जे तक दयनीय हैं।

मोदी ने अपनी सरकार के लगभग चार माह ही पूरे किए हैं। राष्ट्रीय हताशा विदा हुई है, आशावाद और उत्साह बढ़ा है। मुद्रास्फीति घटी है। रुपये की कीमत मजबूत हुई है। विदेश नीति की प्रशंसा हो रही है। जन-धन योजना को लेकर उत्साह है। सरकारी कार्य संस्कृति बदल गई है। उत्तर प्रदेश में सपा को बढ़त मिली है। भाजपा अपनी 7 विधानसभा सीटें हार गई है। भाजपा को झटका लगा है। सपा स्वाभाविक ही खुश है, लेकिन मूलभूत प्रश्न यह है कि यदि चुनाव परिणाम मोदी सरकार के विरुद्ध हैं और सपा सरकार के पक्ष में हैं तो क्या मतदाताओं ने राज्य की अराजकता, ध्वस्त विद्युत आपूर्ति, किसानों की बदहाली और प्रशासनिक तंत्र की विफलता के पक्ष में वोट दिया है और मोदी सरकार के कार्यों व आशावादी माहौल के बावजूद सभी मोर्चे पर असफल सपा सरकार को विजयी बनाया है। ऐसा निष्कर्ष मतदाताओं के विवेक का अपमान होगा। चुनाव नतीजों को मोदी सरकार के कामकाज से जोड़ना अन्याय है। भाजपा विरोधी दल और वरिष्ठ नेता भी ऐसी ही टिप्पणियां कर रहे हैं। भाजपा असम में बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में भी उसने एक सीट जीती है। यह बड़ी उपलब्धि है। निराश हताश और पराजित कांग्रेस को भी आशावाद मिला है। गुजरात और राजस्थान में कांग्रेस को जीने लायक आशावाद मिला है।

मोदी ने अपनी सरकार के लगभग चार माह ही पूरे किए हैं। राष्ट्रीय हताशा विदा हुई है, आशावाद और उत्साह बढ़ा है। मुद्रास्फीति घटी है। रुपये की कीमत मजबूत हुई है। विदेश नीति की प्रशंसा हो रही है। जन-धन योजना को लेकर उत्साह है। सरकारी कार्य संस्कृति बदल गई है। उत्तर प्रदेश में सपा को बढ़त मिली है। भाजपा अपनी 7 विधानसभा सीटें हार गई है। भाजपा को झटका लगा है। सपा स्वाभाविक ही खुश है, लेकिन मूलभूत प्रश्न यह है कि यदि चुनाव परिणाम मोदी सरकार के विरुद्ध हैं और सपा सरकार के पक्ष में हैं तो क्या मतदाताओं ने राज्य की अराजकता, ध्वस्त विद्युत आपूर्ति, किसानों की बदहाली और प्रशासनिक तंत्र की विफलता के पक्ष में वोट दिया है और मोदी सरकार के कार्यों व आशावादी माहौल के बावजूद सभी मोर्चे पर असफल सपा सरकार को विजयी बनाया है। ऐसा निष्कर्ष मतदाताओं के विवेक का अपमान होगा। चुनाव नतीजों को मोदी सरकार के कामकाज से जोड़ना अन्याय है। भाजपा विरोधी दल और वरिष्ठ नेता भी ऐसी ही टिप्पणियां कर रहे हैं। भाजपा असम में बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में भी उसने एक सीट जीती है। यह बड़ी उपलब्धि है।

मतदाताओं ने किसी भी दल को पुरस्कृत या उपकृत नहीं किया और न ही किसी दल को तिरस्कृत। यहां समूचे दलतंत्र को संदेश है कि जनहित की सोचो। मतदाताओं का संदेश सुनो, गुनो, पुनर्विचार करो। भाजपा से अपेक्षाएं ज्यादा हैं। भाजपा

बाकी दलों से कई अर्थों में भिन्न भी है। इसकी छोटी चूक भी बर्दाश्त के बाहर होती है। भाजपा केंद्र की सत्ता में है। मोदी विशेष कार्यसंस्कृति वाले प्रधानमंत्री हैं। देश उनके प्रभाव में नई राजनीतिक संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। भाजपा विचार आधारित कार्यकर्ता आधारित सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। प्रख्यात दार्शनिक नीत्से ने कहा था- 'पर्वतारोहण में हम जितनी अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, वायु उतनी ही विरल होती है। ऐसी ऊंचाई पर जाकर जिनका श्वास नहीं उखड़ता वे विरले हैं।' भाजपा राजनीतिक पर्वतारोहण में शिखर ऊंचाई पर है। अब अतिरिक्त सावधानी और समन्वय की आवश्यकता है। ऐसे झटकों से भाजपा को लाभ ही होने वाला है। राजनीतिक पंडितों को निराशा ही हाथ लगेगी। भाजपा असाधारण राजनीतिक दल है। विश्व राजनीति के शोधार्थियों का आकर्षण। इसकी बढ़त विश्व राजनीति का आश्चर्य है। यूरोप, अमेरिका या एशियाई चीन के विद्वान भाजपा से 2014 जैसी चुनावी जीत की अपेक्षा नहीं रखते थे। प्रतिबद्ध राजनीतिक विवेचकों ने मोदी का भयावह व्यक्तित्व गढ़ा था। अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। भाजपा का विचार बढ़ा, विचार का प्रचार बढ़ा, प्रचार प्रसार का भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़ा। डेनमार्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थामस ब्लूम हांसेन ने 14 बरस पहले ही भाजपा की ताकत का अनुमान लगाया था। उन्होंने सैफ्रन वेव में लिखा था-'भाजपा-हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन ने भारतीय मध्यवर्ग की इच्छा और बेचैनी को रूपांतरित करने में सफलता पाई है। इसके साथ ही आम आदमी में भी सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रशक्ति का बोध जगाया है।' उपचुनाव के परिणाम भाजपा के ऐसे काम को झुठला नहीं सकते। दिक्कत प्रतिबद्ध विवेचकों की व्याख्या में है। एक अंग्रेजी चैनल में एक जानकार ने मोदी सरकार को हराकर ही दम लिया। हालांकि उन्हें यूपी के चरखारी विधानसभा क्षेत्र का नाम भी ठीक से पता नहीं था।

कुछ राजनीतिक पंडित उपचुनावों के नतीजों का पानी हरियाणा और महाराष्ट्र के आगामी चुनाव तक उलीच रहे हैं। भाजपा के नुकसान वाले आंकड़े और ग्राफिक्स तैयार हैं। विचार स्वातंत्र्य का यही रसरंजन जनता का मनोरंजन है, लेकिन तथ्य दूसरे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की कांग्रेसी सरकारें हद दर्जे तक अलोकप्रिय हैं। यहां भाजपा ही विकल्प है।

राष्ट्र निर्माण दीर्घकालिक कर्म साधना है और राजनीति अल्पकालिक सेवा। राजनीति में दीर्घकाल नहीं होता। हरेक पांच साल बाद इसकी परीक्षा है। सभी चुनाव एक ही मानसिक धरातल पर नहीं होते। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय प्रश्न और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां भी मुद्दा होती हैं। विधानसभा चुनाव में राज्य स्तरीय विकास और सुशासन के मुद्दे उठते हैं। मतदाता ऐसे चुनावों में केंद्र या राज्य का विचार करते हैं, लेकिन उपचुनाव में उनके सामने ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। वे शुद्ध स्थानीय होते हैं, स्थानीयता में प्रबंधन का लाभ मिलता है, कुप्रबंधन से हानि होती है। प्रबंधन में जाति, पंथ, मजहब और प्रशासनिक तंत्र की प्रतिबद्धता को भी जोड़ा घटाया जा सकता है। इसलिए नतीजों को मोदी सरकार से मोहभंग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। परिणाम सपा सरकार की अराजकता के पक्ष में भी नहीं हैं। वे गुजरात या राजस्थान की सरकार के पक्ष या विपक्ष में कोई रायशुमारी भी नहीं हैं। वे शुद्ध स्थानीय लोकमत हैं। दलतंत्र शोक मनाए या खुशी, उसका अपना आंतरिक मामला है। उपचुनाव के नतीजों में खुशफहमी का कोई आधार नहीं। ऐसी खुशफहमी गलतफहमी है। कांग्रेस जरूरत से ज्यादा खुश है। सपा की खुशी मैनपुरी से लोकसभा पहुंच गई है। अब एक और युवा परिजन लोकसभा में हैं।

कुछ राजनीतिक पंडित उपचुनावों के नतीजों का पानी हरियाणा और महाराष्ट्र के आगामी चुनाव तक उलीच रहे हैं। भाजपा के नुकसान वाले आंकड़े और ग्राफिक्स तैयार हैं। विचार स्वातंत्र्य का यही रसरंजन जनता का मनोरंजन है, लेकिन तथ्य दूसरे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की कांग्रेसी सरकारें हद दर्जे तक अलोकप्रिय हैं। यहां भाजपा ही विकल्प है। कुछेक टिप्पणीकार उपचुनाव नतीजों को उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक प्रभावी मान रहे हैं। प्रश्न है कि यूपी की अराजकता, सांप्रदायिक हिंसा, राज्य तंत्र की विफलता, ध्वस्त विद्युत आपूर्ति से त्राहि-त्राहि करती जनता क्या उपचुनाव परिणामों की प्रेरणा से ही सपा के साथ खड़ी होगी? या उपचुनाव से भाग खड़ी बसपा के साथ? या हर मोर्चे पर संघर्ष करती भाजपा के साथ? जनसंदेश ने भाजपा को सावधान किया है और बाकी दलों को सक्रिय रहने का संदेश दिया। भारतीय मतदाता हरेक जनादेश में दलतंत्र को आत्म विश्लेषण का ही संदेश देते हैं। सुनिए। गुनिए। तद्नुसार काम कीजिए। ■

(लेखक, उप्र विधान परिषद के सदस्य हैं।) (साभार- दै. जागरण)

मजबूत नेतृत्व का असर

✍ गुरचरण दास

भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी का चुनाव बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करने, बेहतर शासन देने और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए किया। अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वह इन तीनों ही वादों को पूरा कर सकेंगे। उनके कार्यकाल के शुरुआती तीन-साढ़े तीन माह यही दर्शाते हैं कि वह किस तरह इन लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए सरकार को बहुत सजग रहना होगा। आज की तिथि तक मोदी का उल्लेखनीय योगदान यही है, कि सरकार में सभी स्तरों पर कार्यो के निपटारे में चमत्कारिक सुधार आया है। कांग्रेस शिकायत कर रही है कि मोदी सरकार के पास नए विचारों का अभाव है और वह संप्रग सरकार के विचारों की नकल कर रही है। हालांकि सच्चाई यही है कि विचार किसी के भी पास हो सकते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कुछ लोग ही कर सकते हैं।

जो लोग मोदी सरकार द्वारा बड़े सुधार न किए जाने से निराश हैं, वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या विचारों, नीतियों और कानूनों का अभाव नहीं, बल्कि इनका खराब क्रियान्वयन है। क्रियान्वयन में कमजोरी ही वह मुख्य कारण जिससे भारत की विकास दर पिछले तीन वर्षो में गिरती गई। पहले दिन से ही मोदी ने अपेक्षाओं को काफी ऊंचा रखा। उन्होंने सुरक्षित रास्ते का अनुसरण करने से इन्कार किया और इस वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने का ऊंचा लक्ष्य तय किया और कहा कि वह इसे हासिल कर सकते हैं। वह निर्धारित लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, इसमें संदेह है, लेकिन उद्देश्य को लेकर एक नई सोच आई है तथा केंद्र समेत तमाम राज्यों और यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रुख में स्पष्ट बदलाव परिलक्षित होने लगा है। इसका प्रमाण प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप अथवा परियोजना निगरानी समूह के गठन से लगाया जा सकता है, जो सैंकड़ों की संख्या में रुकी पड़ी परियोजनाओं के अवरोधों को हटाने का प्रयास करेगा। इससे केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी, राज्य सरकारें और बिजनेस वर्ग भी काफी उत्साहित है। हालांकि इसका गठन पहले ही हो गया था, लेकिन इस समूह को ऊर्जा तब मिली जब मोदी सत्ता में आए। ऐसी रिपोर्ट हैं कि पिछली सरकार में जो अधिकारी परियोजनाओं को रोकने में बाधक बन रहे थे और उदासीन रवैया अपनाए हुए थे अब वही अधिकारी जोशपूर्वक इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति दे रहे हैं।

अब चुनौतियां और बाधाएं खत्म हो रही हैं। एक समय इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं वर्षो तक रुकी रहने के कारण उद्यमी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए थे और बैंकों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता था। स्थिति कुछ ऐसी थी कि पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद भी बैंक वित्तीय मदद देने से इन्कार कर देते थे। नए भूमि अधिग्रहण कानून ने भी तमाम मुश्किलों को खड़ा करने का काम किया। तमाम राज्यों ने जानकारी दी कि नया कानून अस्तित्व में आने के बाद सभी तरह की भूमि की खरीद-बिक्री का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जब आप सैंकड़ों की संख्या में रुकी परियोजनाओं के संदर्भ में इस समस्या का आकलन करते हैं तो आप सोचने को विवश होंगे और संप्रग सरकार की घटिया विरासत को लेकर देश की दुर्दशा पर रोएंगे या दुखी होंगे। इस

तमाम राज्यों ने जानकारी दी कि नया कानून अस्तित्व में आने के बाद सभी तरह की भूमि की खरीद-बिक्री का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जब आप सैंकड़ों की संख्या में रुकी परियोजनाओं के संदर्भ में इस समस्या का आकलन करते हैं तो आप सोचने को विवश होंगे और संप्रग सरकार की घटिया विरासत को लेकर देश की दुर्दशा पर रोएंगे या दुखी होंगे। इस मामले में हमें एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करने वाली मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हाथ खड़े करने के बजाय अधिकारियों को उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया और नतीजा यह हुआ कि सब कुछ चलता है की प्रवृत्ति वाले नौकरशाह अब उल्लेखनीय काम कर रहे हैं।

मामले में हमें एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करने वाली मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हाथ खड़े करने के बजाय अधिकारियों को उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया और नतीजा यह हुआ कि सब कुछ चलता है की प्रवृत्ति वाले नौकरशाह अब उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। मोदी द्वारा हाथ में ली गई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एकल खिड़की का प्रावधान बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा। भारत में कोई उद्योग शुरू करने के लिए तकरीबन 60 क्लीयरेंस लेने की जरूरत पड़ती है, इनमें से 25 केंद्र के स्तर पर और 35 राज्य स्तर पर होती हैं, लेकिन डिजिटलीकरण के बाद यह सारे काम एक ही परियोजना निगरानी समूह द्वारा संभव होंगे। पूर्ण डिजिटलीकरण के बाद उद्यमी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने काम की प्रगति की जानकारी इंटरनेट पर देख सकेंगे। इससे यह भी पता चलेगा कि कौन अधिकारी फाइलों को रोक रहा है। इस तरह उद्यमियों के लिए एकल खिड़की का सपना साकार हो सकेगा। तीव्र क्रियान्वयन से रोजगार सृजन भी तेज होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में नियुक्तियों में 20 फीसद की बढ़ोतरी हुई है जो पिछले पांच वर्षो में बेहतरीन प्रदर्शन है।

मोदी भाग्यशाली रहे कि अप्रैल से जून तिमाही में जीडीपी विकास दर बेहतर रही। यह अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी और उच्च विकास को दर्शाती है। स्पष्ट है कि रोजगार का अधिक सृजन होगा। मोदी को तेज क्रियान्वयन के खतरे के प्रति भी सजग रहना होगा। जन-धन योजना एक बेहतरीन कार्यक्रम है, जिससे सभी भारतीयों को बैंक खाते की सुविधा मिलेगी और निर्धन वर्ग से संबंधित योजनाओं के लिए नकदी हस्तांतरण के माध्यम से बड़ी मात्रा में सरकारी धन की बचत होगी। हालांकि यह योजना बैंकों पर अत्यधिक निर्भर है, जो गरीबों का खाता खोलने के लिए बहुत इच्छुक नहीं हैं। बैंक तभी रुचि लेंगे जब सब्सिडी की वर्तमान व्यवस्था को खत्म किया जाए और धन का प्रवाह गरीबों के लिए खुले इन खातों में किया जाए। इसमें समय लगेगा।

जहां तक मोदी की ओर से शासन में सुधार, क्लीयरेंस में पारदर्शिता के माध्यम से जवाबदेही के वादे की बात है तो निश्चित रूप से इससे लालफीताशाही खत्म होगी। सिंगापुर, अमेरिका जैसे तमाम देशों में बिजनेस शुरू करने में 3 से 5 दिन लगता है, जबकि भारत में 75 से 90 दिन। इसी कारण बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का स्थान 134वां है। तीसरा मुद्दा महंगाई पर नियंत्रण का है। मोदी सरकार अतिरिक्त पड़े भंडारों से खाद्यान्नों को बेच रही है जिससे इनके दाम गिरे हैं, लेकिन यदि आयात शुल्क घटाए जाते हैं और महत्वपूर्ण खाद्यान्नों व सब्जियों आदि पर से गैर टैरिफ बाधाओं को खत्म किया जाता है तो वह इस तीसरे लक्ष्य को भी हासिल कर सकेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हुए हैं और मानसून का बहुत खराब न रहना मोदी के लिए लाभदायक है। यदि वह सरकारी खर्चों में कटौती कर सके तो महंगाई और कम होगी। ध्यान रहे संप्रग सरकार में सरकारी खर्च महंगाई बढ़ने की एक मुख्य वजह थी।

मोदी कार्यकाल के तीन महीने बताते हैं कि कैसे एक प्रभावी नेतृत्व बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से सरकार की क्षमता को बढ़ा देता है। कम महंगाई के साथ उच्च विकास को बनाए रखने के लिए मोदी को दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों पर अमल करना होगा। भ्रष्टाचार पर प्रहार करने और बेहतर शासन के लिए उन्हें नौकरशाही, पुलिस और न्यायपालिका में सुधार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मोदी को केसरिया ब्रिगेड पर नियंत्रण करना होगा, जो उनके तीन वादों को पूरा करने में अनावश्यक अड़चन पैदा कर सकती है।■ *(साभार- दै. जागरण)*

महंत अवैद्यनाथ नहीं रहे

चार बार सांसद रहे और श्रीराम जन्म भूमि आंदोलन के अग्रणी नेता गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ का 12 सितंबर 2014 को गुड़गांव स्थित अस्पताल में निधन हो गया वे 96 साल के थे।

भाजपा अध्यक्ष का शोक संदेश

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर एवं पूर्व सांसद महंत अवैद्यनाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री शाह ने कहा कि महंत अवैद्यनाथ को अध्यात्म, मानव मूल्यों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के संरक्षक के तौर पर हमेशा याद किया जायेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रचार-प्रसार में भी अहम भूमिका निभायी। उनके प्रेरणादायी विचार सदैव जन-जन का मार्गदर्शन करते रहेंगे।■

पूर्व प्रधानमंत्री की लापरवाही

✍ ए. सूर्यप्रकाश

भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था, लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), द्वारा किए गए परिश्रम तथा पूर्व सीएजी विनोद राय की दृढ़ता एवं हठयोग की बदौलत, ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह का असली रूप सामने लाने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। भारत की जनता के सामने जो कडुवा सच अब आ रहा है वो यह है कि एक महान अर्थशास्त्री और सत्यनिष्ठापूर्ण व्यक्ति न होकर, पूर्व प्रधानमंत्री का समष्टि आर्थिक प्रबंधन विनाशकारी साबित हुआ, और निश्चित रूप से उन्होंने पद पर बने रहने के लिए भयावह किस्म के समझौते किए। परिणामस्वरूप, उन्होंने राष्ट्रीय हित से समझौता किया, सरकारी कोष को घाटा दिया और भारत के आर्थिक पतन में अच्छा खासा योगदान दिया।

2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला सामने आने के बाद देश की जनसंख्या के एक बड़े तबके को श्री सिंह की विश्वसनीयता पर संदेह होना शुरू हो गया था, लेकिन जनता ने उन्हें संदेह का लाभ दिया। हालांकि, जब 2जी घोटाला और कोलगेट घोटाला सामने आया, जनता के मन में सरकार का नेतृत्व करने की श्री सिंह की क्षमता को लेकर संदेह होना शुरू हो गया। 2013 की शुरुआत से यह स्पष्ट हो गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सूची में राष्ट्रीय हित शामिल नहीं था।

ऐसा लगता है कि सत्ता में बने रहने की आकांक्षा से मनोग्रहीत होकर उन्होंने अपने राजनीतिक आकाओं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, व कुछ गठबंधन सहयोगियों को खुश करने के लिए अक्षम्य फैसले लिए। जो प्रमाण सामने हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि देश ने निस्संदेह संपूर्ण दशक के लिए मनमोहन सिंह को पीएम के रूप में स्वीकार करने की भारी कीमत चुकाई है।

सीएजी ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन करते समय नीलामी की प्रक्रिया अपनाने में सरकार की विफलता को सीएजी ने जान लिया और राजकोष को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ जबकि उसी तरह कोयला खंडों के आवंटन में सही तरीका न अपनाने का परिणाम 1.86 लाख करोड़ के नुकसान के रूप में सामने आया। जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, श्री सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने तत्कालीन सीएजी श्री राय और लेखा परीक्षा संस्था की निंदा की। मगर सरकार और कांग्रेस द्वारा अहम संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने के कांग्रेस के प्रयासों को जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया।

हालांकि कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का सबब बने ये भूत श्री राय द्वारा अपनी आने वाली पुस्तक 'नाट जस्ट ऐन एकाउंट' के विमोचन के अवसर पर मीडिया से बातचीत करने के निर्णय के बाद पुन: मंडराने लगे हैं। इस समय, उनके द्वारा श्री मनमोहन सिंह की सरकार और कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों की गम्भीरता इतनी है कि वे चुनावी पराजय से परे जाकर दंड दिए जाने योग्य हैं। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि उनकी मुलाकात श्री सिंह से तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ कोलगेट पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बातचीत करने के लिए हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने कार्रवाई नहीं की। बाद में, श्री सिंह 2004 में स्वयं बड़ी प्राप्तियों से वाकिफ थे जो कम्पनियों ने कोयला खंड आवंटनों के लिए दी थीं। मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। श्री राय के हालिया मीडिया खुलासे ने कांग्रेस के परम्परागत मुखर नेताओं को सन्न कर दिया है, लेकिन इसने कमलनाथ सरीखे

2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला सामने आने के बाद देश की जनसंख्या के एक बड़े तबके को श्री सिंह की विश्वसनीयता पर संदेह होना शुरू हो गया था, लेकिन जनता ने उन्हें संदेह का लाभ दिया। हालांकि, जब 2जी घोटाला और कोलगेट घोटाला सामने आया, जनता के मन में सरकार का नेतृत्व करने की श्री सिंह की क्षमता को लेकर संदेह होना शुरू हो गया। 2013 की शुरुआत से यह स्पष्ट हो गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सूची में राष्ट्रीय हित शामिल नहीं था।

मजबूत जड़ों वाले राजनेताओं की अंतर्चेतना को जगा दिया है, जो श्री सिंह की कैबिनेट के सदस्य थे। कमलनाथ ने यह माना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और आगाह किया था कि, 2जी आवंटन में बहुत कुछ चल रहा है। कमलनाथ सरीखे मंत्री चाहते थे कि मनमोहन सिंह कदम उठाएं और किसी मंत्री समूह से मामले की जांच करवाएं लेकिन श्री सिंह ने चेतावनी को अनदेखा कर दिया।

समान रूप से आहत करने वाला है श्री राय का नया खुलासा कि तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल, ने 28 के बजाए 68 विमान खरीदने हेतु एयर इंडिया पर दबाव डाला था और तब से पांच वर्ष बाद, उनमें से बहुत से विमान एयर इंडिया द्वारा मूल कीमत के 20 प्रतिशत मूल्य पर बेच दिए गए थे। पूर्व सीएजी द्वारा जाहिर की गई ये नयी बातें इस सिद्धांत को विश्वसनीयता प्रदान करती हैं कि श्री सिंह का आचरण दुर्बलता और धूर्तता के बीच झूलता रहा।

कोलगेट और उसके व्यापक परिणामों पर वापस लौटे तो यह कहा जा सकता है कि यदि श्री सिंह ने कोयला खंडों को आवंटित करने की पारदर्शी और निष्पक्षतापूर्ण पद्धतियां अपनाने पर जोर दिया होता, तो केंद्र सरकार के हाथों में 1.86 लाख करोड़ रुपए आ जाते।

लेकिन, यह तो शुरुआत करने वालों के लिए है। मगर जो हमें देखने की जरूरत है वो है श्री सिंह की जानबूझकर एवं सोची समझी अनिर्णय की स्थिति का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब यह कहा जाने लगा है कि पूर्व कोयला खंड उन निजी कम्पनियों को आवंटित कर दिए गए जिनका कोयला उत्पादित करने का कोई इरादा नहीं था। वे सिर्फ कोयले का भंडार

वित्त मंत्रालय की अनेक वर्षों से जिम्मेदारी सम्भाल रहे व्यक्ति को बिजली उत्पादन पर कोयला खनन न होने के प्रभाव का जरा भी अनुमान नहीं था। ऐसी गैरजिम्मेदारी और दम्भ के शायद ही कोई समानांतर उदाहरण होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि मतदाताओं ने लोकसभा में कांग्रेस को एक छोटे समूह में बदल दिया। केंद्रीय बिजली एवं कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नवीनतम स्थिति रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि देश ने श्री सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का भारी खामियाजा भुगतान है। वर्तमान समय में 280 मिलियन नागरिकों को बिजली नहीं मिल रही है।

तैयार कर खानों को बेचकर भारी मुनाफा कमाना चाहती थीं। श्री सिंह ने संविदाएं निरस्त न करके निजी कम्पनियों की इन संदिग्ध योजनाओं को मौन स्वीकृति दे दी। कहा जाता है कि 2004 से कोयला खंड आवंटन के बाद खनन केवल एक ही खंड में शुरू हो पाया। इसके परिणामस्वरूप देश के तमाम ताप बिजलीघरों में कोयले की कमी हो गई जिसके फलस्वरूप बिजली उत्पादन में कमी आई तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों चे नुकसान पहुंचा। इसके कारण उत्पादन में कमी आई, युवाओं की नौकरियां घटीं और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में चिन्ताजनक गिरावट आई। इसके बावजूद श्री सिंह के कैबिनेट मंत्री अरक्षणीय चीजों का बचाव करते रहे। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने असाधारण रूप से दावा किया कि कोयले की खुदाई न होने के कारण देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

दूसरे शब्दों में, वित्त मंत्रालय की अनेक वर्षो से जिम्मेदारी सम्भाल रहे व्यक्ति को बिजली उत्पादन पर कोयला खनन न होने के प्रभाव का जरा भी अनुमान नहीं था। ऐसी गैरजिम्मेदारी और दम्भ के शायद ही कोई समानांतर उदाहरण होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि मतदाताओं ने लोकसभा में कांग्रेस को एक छोटे समूह में बदल दिया। केंद्रीय बिजली एवं कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नवीनतम स्थिति रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि देश ने श्री सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का भारी खामियाजा भुगतान है। वर्तमान समय में 280 मिलियन नागरिकों को बिजली नहीं मिल रही है।

निश्चित रूप से ऐसे प्रधानमंत्री को दंड देने का कानून होना चाहिए जो पद पर रहते समय अपनी लापरवाही के कारण अथवा जानबूझकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। जब हमारे यहां आटोमोबाइल वाहन चालकों, सिविल इंजीनियरों आदि के लापरवाही भरे व्यवहार पर दंड की व्यवस्था है तो देश के प्रधानमंत्री को क्यों छोड़ दिया जाए?

एक विधि शब्दावली में लापरवाही को व्यावहारिक या तार्किक व्यक्ति द्वारा दी गई परिस्थितियों में दूसरों के प्रति देखभाल करने में विफलता या ऐसी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो कोई तार्किक व्यक्ति न करता। इसलिए श्री मनमोहन सिंह न केवल संयोगवश बने प्रधानमंत्री थे बल्कि जैसा श्री संजय बारू ने उनके बारे में कहा है, वे एक लापरवाह प्रधानमंत्री भी थे। हमें उनके अभियोजन के रास्ते अवश्य तलाश करने चाहिए। ■

(साभार- पायनियर)

सबका विकास : हमारा आर्थिक दर्शन

✍ जयंत सिन्हा

हर सरकार कहती है कि वह प्रत्येक देशवासी को समृद्धि प्रदान करेगी, सब वर्गों के लोगों को नौकरियां देगी और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और भलाई की रक्षा करेगी। सभी राजनेताओं और चुनावी घोषणापत्रों द्वारा इन नेक इरादों का विवरण किया जाता है। परन्तु जैसे अटल जी ने एक समय एक अर्थशास्त्री से पूछा था, जब वह अर्थशास्त्री भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के उपाय निरंतर बताते चले जा रहे थे। ''यह होगा कैसे?''

हमारा आर्थिक दर्शन राष्ट्रवाद पर आधारित होगा। अर्थात् भारत माता को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे, जिससे भारत विश्व गुरु बन पायेगा। हमारी सख्त और मृदु शक्ति, यानि हार्ड और सॉफ्ट पावर, विश्व में अद्वितीय होंगे। उस लक्ष्य की ओर, हमारे आर्थिक दर्शन में कुछ सिद्धांत प्रतिष्ठापित होने चाहिए: (1) राजकोषीय विवेक, नाकि नासमझ लोकलुभावनवाद, (2) मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, (3) स्वस्थ्य, निपुण और उद्यमी वर्कफोर्सय, (3) मेक इन इन्डिया और, इसलिए, (5) गरीबों की सरकार बनना।

कैसे प्रदान करेंगे हम सबको समृद्धि? क्या करेंगे हम महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी रोकने के लिए? कितनी विश्वसनीय हैं हमारी योजनायें? क्या उन्हें अगले कुछ वर्षों में कार्यान्वित किया जा सकता है? क्या राज्य के पास इन योजनाओं पर अमल करने की क्षमता और संसाधन हैं? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका होगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी? अगर आजाद भारत की हर सरकार को कठिनाइयाँ हुई हैं, तो हम क्यों सफल होंगे? भारत के हर नागरिक को हमसे ऐसे सवाल पूछने चाहिए।

इन सभी सवालों के जवाब इस लेख में देना मुमकिन नहीं है। वास्तव में, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से जवाब देने के लिए कई वर्षों की चर्चा और विश्लेषण की आवश्यकता है। इसके बजाय हमें एक वैचारिक रूपरेखा रखनी चाहिए, मसलों पर सोचने का एक तरीका, जो मार्गदर्शन करे हमारे दृष्टिकोण का, हमारी नीतियों का और अंततः सरकार के हर स्तर पर लिए गए निर्णयों का। कुल मिलाकर, हमें एक सुसंगत आर्थिक दर्शन को स्पष्टता से व्यक्त करना चाहिए, जिससे तर्कसम्मत रूप से हमारे निर्णय लेने के सिद्धांतों की स्थापना होगी और हमें अपनी प्राथमिकताएँ जानने और मुश्किल विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

यह स्पष्ट है कि हमारा आर्थिक दर्शन राष्ट्रवाद पर आधारित होगा। अर्थात् भारत माता को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे, जिससे भारत विश्व गुरु बन पायेगा। हमारी सख्त और मृदु शक्ति, यानि हार्ड और सॉफ्ट पावर, विश्व में अद्वितीय होंगे। उस लक्ष्य की ओर, हमारे आर्थिक दर्शन में कुछ सिद्धांत प्रतिष्ठापित होने चाहिए: (1) राजकोषीय विवेक, नाकि नासमझ लोकलुभावनवाद, (2) मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, (3) स्वस्थ्य, निपुण और उद्यमी वर्कफोर्सय, (3) मेक इन इन्डिया और, इसलिए, (5) गरीबों की सरकार बनना।

हम राजकोषीय विवेक का अनुसरण करते हैं, नाकि नासमझ लोकलुभावनवाद का। अटल जी की सरकार ने 2004 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) को कार्यान्वित करके यह सुनिश्चित करना चाहा था कि विशेष परिस्थितियों के अलावा, सरकारी घाटे देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत से अधिक ना हों। यूपीए सरकार ने झटपट FRBM देश-निर्देशों को त्याग दिया और विभिन्न सब्सिडी और हकदारी कार्यक्रमों के बोझ से राजकोषीय घाटों को जीडीपी के 6.4 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। हमारे पहले ही बजट में हमने 3 प्रतिशत तक पहुँचने की रूपरेखा प्रस्तुत की है। हम यह भी मानते हैं कि चालू खाता घाटे को जीडीपी के 2 प्रतिशत के नीचे रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अधिशेष स्तर के करीब आ सकें। इन दो मापदंडों के नियंत्रण से, मुद्रास्फीति को स्वीकारीय स्तर पर रखना और रूपए को स्थिर रखना मुमकिन हो सकेगा। ऐसी विवेकी नीतियाँ देश में वृहद-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेंगी

और सरकार के आर्थिक प्रबंधन में पुन: विश्वास लायेंगी। परिणामस्वरूप, हम घरेलू बचत को वित्तीय प्रणाली में आकर्षित कर पा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि विदेशी पूंजी का अच्छा प्रवाह बने।

प्रधान मंत्री मोदी जी ने कई बार कहा है कि वे मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी न्यूनतम शासक और अधिकतम शासन, में विश्वास रखते हैं। सरकार की भूमिका प्रभावशाली, कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने की होगी, जिससे सारे निवासी अपनी गतिविधियाँ सुचारू रूप से कर सकेंगे। हमारी सरकार अभी से मंजूरियों की प्राप्ति, पुराने कानून, बोझिल और अनावश्यक प्रक्रियाओं पर कार्यरत है। हम चाहते हैं कि भारत में व्यवसाय करना बिल्कुल सरल हो। साथ ही, हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर उद्यम काफी हद तक पेशेवर रूप से, और बिना राज्य के हस्तक्षेप के काम कर सकें। इसका तात्पर्य यह भी है कि हम प्राइवेट सेक्टर को जहां हो सके वहां प्रोत्साहन देंगे, जिससे वे अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकें। उदाहरण के तौर पर, हम अपनी सेनाओं को उच्च-गुणवत्ता वाले उपकरण मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्र से रक्षा उत्पादन शुरू करवाना चाहते हैं। अंत में, हम एक स्थिर, उम्मीद के मुताबिक टैक्स प्रणाली की स्थापना कर रहे हैं, जिससे व्यवसाय और व्यक्ति टैक्स अधिकारियों से परेशान हुए बगैर सरलता से टैक्स नियमों का अनुपालन कर सकें। हमारे राज्यों में टैक्स मुद्दों पर सामंजस्य होना चाहिए ताकि हम राज्य सीमाओं के आर-पार आसानी से व्यवसाय कर सकें, और पूरा देश एक निर्बाध बाजार बन सके।

भारत के पास दुनिया का श्रेष्ठ जनबल है। हमारी आबादी युवा है, सीखने को इच्छुक है और श्रम करने को तत्पर है। हमें अपने जनबल को निपुणता, क्षमता और नैतिकता से लैस करना होगा जिससे वे विश्व स्तर पर ईमानदारी और प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। इसके लिए हमें अपने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना होगा। हमारे विद्यालयों में हर किस्म की सुविधायें होनी चाहिए, जैसे कक्षाएं, कंप्यूटर, टॉयलेट और दोपहर का भोजन। हमारे शिक्षकों को अच्छे वेतन के साथ-साथ उत्तम ढंग से पढ़ाने के लिए संसाधन मिलने चाहिए। हमारे विश्व-विद्यालयों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। हमारे उच्चतम विश्वविद्यालयों को उद्यमी केंद बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो व्यापारिक एवं सामाजिक नवीनता का सृजन करें, जिससे हमारी अधिकतम जटिल समस्याओं का हल हो पायेगा। इसके अलावा, हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का सघन जाल बनाकर व्यावहारिक कौशल्य प्रदान करना चाहिए।

भारत में 'मेक इन इंडिया' के नारे का जीवंत होना अति-आवश्यक है। जैसे-जैसे हमारा देश विकसित होते जा रहा है, वैसे-वैसे हमें विनिर्माण, कृषि, ऊर्जा और जल-आपूर्ति को लेकर आत्म-निर्भर होने की जरूरत है। विश्व के अन्य देशों से हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तेल और अन्य सामग्री का आयात नहीं करते रह सकते। हमारा घरेलू बाजार बहुत जल्द लगभग हरेक सामान एवं सेवा के लिए दुनिया के मुख्य 3 बाजारों में गिना जाएगा। हमें इस सामान को भारत में बनाकर दुनिया भर में निर्यात करने का पूरा प्रयत्न करना होगा। साथ ही, नवीन तकनीकों का उपयोग कर हमें खाद्य पदार्थ, जल और ऊर्जा में आत्म-निर्भर बनना पड़ेगा। क्योंकि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से इन वस्तुओं पर बहुत तनाव पड़ेगा। हमें अपने ढांचागत क्षेत्र को तेजी से सुधारना चाहिए, ताकि हम भारत में निर्माण कर सकें। हमें रेल एवं सड़क जाल पर काफी निवेश करना होगा, बिजली आपूर्ति के लिए अनिवार्य पावर प्लांट और ग्रिड खड़े करने होंगे और कृषि सुविधायों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना करके अप्रत्याशित मानसून से सुरक्षा हासिल करनी होगी।

हमारी सरकार गरीबों के लिए चलती है। सरकार के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। परन्तु हम एक व्यापार-समर्थक सरकार भी हैं। इन

शेष पृष्ठ 25 पर

प्रधान मंत्री मोदी जी ने कई बार कहा है कि वे मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी न्यूनतम शासक और अधिकतम शासन, में विश्वास रखते हैं। सरकार की भूमिका प्रभावशाली, कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने की होगी, जिससे सारे निवासी अपनी गतिविधियाँ सुचारू रूप से कर सकेंगे। हमारी सरकार अभी से मंजूरियों की प्राप्ति, पुराने कानून, बोझिल और अनावश्यक प्रक्रियाओं पर कार्यरत है। हम चाहते हैं कि भारत में व्यवसाय करना बिल्कुल सरल हो।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर उभरा भारत

✍ डॉ. शिव शक्ति बक्सी

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई गति लाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा किए गए विदेश नीति संबंधी पहलों से भारत विश्व पटल पर अपना उचित स्थान बनाने की ओर बढ़ चला है। उनके सबसे कठोर आलोचक भी अब यह मानने को विवश हो गए हैं कि परस्पर लाभदायक कदमों से मजबूत होते विदेशी संबंध भारत को आने वाले दिनों में जबरदस्त लाभ पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी इस मंशा का उसी दिन प्रकट कर दिया था जब उन्होंने अपने शपथ-ग्रहण समारोह में दक्षेस देशों के नेताओं को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। उनके इस कदम का हर ओर स्वागत हुआ जिससे परस्पर लाभदायक दूरगामी संबंधों के लिए सद्भावनापूर्ण वातावरण का निर्माण हुआ। इससे यह भी उम्मीद बंधी कि भारत दक्षिण एशिया में इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है, इसके साथ ही नरेन्द्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कदमों ने भारत के विश्व मंच पर उभरने का मार्ग प्रशस्त किया है।

दक्षेसः जहां तक दक्षेस देशों का प्रश्न है, वह कदम जो शुरू में प्रतीकात्मक लग रहा था, अब एक बड़े नीतिगत फैसले का अंग जान पड़ता है। यह निर्णय दक्षेस देशों को शपथ-ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने तक ही सीमित नहीं था बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पद ग्रहण के तुरंत बाद इन देशों के नेताओं से अलग-अलग मिलकर उनके साथ परस्पर-सरोकारों पर चर्चा भी की। आशा और सद्भाव का माहौल देखने में आया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की तथा दोनों ने उपहारों का आदान-प्रदान करने के साथ व्यापार पर जोर दिया तथा नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद का प्रश्न उठाया। परन्तु दुर्भाग्य से इसे भेंट से हुई प्रगति गवां दी गई जब भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त कश्मीर के अलगाववादियों से मिलने पर अड़े रहे तथा भारत को बाध्य होकर आगे की बातचीत रोकनी पड़ी। परन्तु प्रधानमंत्री के नेपाल एवं भूटान यात्रा ने सही दिशा में संबंधों को बढ़ाने के लिए वातवरण तैयार किया है। हालांकि भूटान एक छोटा देश है परन्तु नरेन्द्र मोदी ने इसे अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुनकर भारत के लिए इसके महत्व को रेखांकित किया। भारत की इस भावना का भूटान के लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया और वे भारी संख्या में नरेन्द्र मोदी के स्वागत में उमड़ पड़े। इस दौरान जल विद्युत तथा शिक्षा पर दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

प्रधानमंत्री ने अपनी इस मंशा का उसी दिन प्रकट कर दिया था जब उन्होंने अपने शपथ-ग्रहण समारोह में दक्षेस देशों के नेताओं को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। उनके इस कदम का हर ओर स्वागत हुआ जिससे परस्पर लाभदायक दूरगामी संबंधों के लिए सद्भावनापूर्ण वातावरण का निर्माण हुआ। इससे यह भी उम्मीद बंधी कि भारत दक्षिण एशिया में इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है, इसके साथ ही नरेन्द्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कदमों ने भारत के विश्व मंच पर उभरने का मार्ग प्रशस्त किया है।

नेपाल यात्राः पिछले 17 वर्षों में नरेन्द्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेपाल की यात्रा की। उनकी यह यात्रा और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लगभग एक दशक से नेपाल राजनैतिक संकटों के दौर से गुजर रहा है। नरेन्द्र मोदी की इस यात्रा का असर हर नेपाली पर देखने को मिल रहा है जो नेपाली संसद में दिए गए उनके भाषण से भावविभोर हो

गये हैं। 'बुलेट' के ऊपर 'बैलेट' और 'युद्ध' के ऊपर 'बुद्ध' को चुनने पर नेपाल की जनता को बधाई देते हुए उन्होंने यह कहते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि भारत उनके मामलों में हस्तक्षेप करने पर विश्वास नहीं करता तथा जो भी राह नेपाल की जनता चुनती है उसको समर्थन देने में भारत का विश्वास है। यह कहकर कि भारत चाहता है कि नेपाल की प्रगति हिमालय की ऊंचाईयों को छुए, नरेन्द्र मोदी ने हर नेपाली का मन मोह लिया। नरेन्द्र मोदी के नेपाल के संसद को दिए संबोधन पर उपस्थित सांसदों ने कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया तथा अपनी इस यात्रा से हर नेपाली के दिल में भारत के लिए एक जगह बनाने में वे सफल हुए हैं।

ब्रिक्स सम्मेलनः ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील की यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। चूंकि बहुपक्षीय सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी, सभी विश्लेषक इसमें गहरी रुचि रख रहे थे। ब्रिक्स में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस 'जीरो-टॉलरेन्स' की बात कही। साथ ही इराक में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता व्यकत करते हुए ब्रिक्स द्वारा इस पर कदम उठाने की वकालत की। ब्रिक्स के द्वारा गठित बैंक पर भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए नरेन्द्र मोदी ने इसका नाम 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' रखने का सुझाव दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया। यह उनकी ही सक्रिय पहल का फल था कि इस बैंक पर किसी एक देश के प्रभुत्व को होने से रोका गया तथा दो वर्षो से अटके इस मामले पर तत्काल निर्णय लेते हुए सदस्य देशों ने इसमें बराबरी की भागीदारी को स्वीकार किया। सौ बिलियन डॉलर के इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा तथा इसका पहला अध्यक्ष भारत से होगा। इस सम्मेलन में नरेन्द्र मोदी को ब्रिक्स देशों के प्रमुखों से मिलकर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मामलों पर चर्चा का अवसर मिला।

ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील की यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। चूंकि बहुपक्षीय सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी, सभी विश्लेषक इसमें गहरी रुचि रख रहे थे। ब्रिक्स में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस 'जीरो-टॉलरेन्स' की बात कही। साथ ही इराक में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता व्यकत करते हुए ब्रिक्स द्वारा इस पर कदम उठाने की वकालत की।

जापान यात्राः अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों द्वारा नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा को अत्यधिक सफल माना जा रहा है। वास्तव में यह भारत-जापान संबंधों में एक लंबी छलांग थी जिससे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच दूरगामी एवं दृढ़ संबंध स्थापित होंगे। यह कहते हुए कि भारत और जापान एक आध्यात्मिक संबंध को साझा करते हैं उन्होंने कहा, 'यह फेविकोल से भी ज्यादा मजबूत जोड़ है'। भारत-जापान संबंध केवल द्विपक्षीय या क्षेत्रीय नहीं पर वैश्विक भी हो सकता है क्योंकि दोनों पक्षों ने संयुक्त सामरिक भागीदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। जापान ने आने वाले पांच वर्षो में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में 35 बिलियन डॉलर निवेश की घोषणा कर भारत के आर्थिक विकास एवं बदलाव के लिए स्वयं का प्रतिबद्ध कर लिया। लेकिन इन बातों से भी अधिक महत्वपूर्ण था कि नरेन्द्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करने में सफल रहे।

चीन के राष्ट्रपति का आगमनः चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा नरेन्द्र मोदी की एक बड़ी उपलब्धि रही। भारत-चीन संबंधों में सीमा विवाद के साथ-साथ अन्य जटिलताओं के कारण विश्लेषकों की इस यात्रा पर पैनी निगाह थी। इससे पूर्व नरेन्द्र मोदी शी जिंगपिंग से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मिलकर सीमा पर हो रहे घुसपैठ का मसला उठाया था जिसे दोनों नेताओं ने सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर बल दिया था। जब शी जिंगपिंग का भारत में पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा था चीनी सैनिक लद्दाख के चुमार इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। नरेन्द्र मोदी ने बिना समय गंवाये इस विषय को जिंगपिंग के समक्ष कड़ाई से उठाया जिस पर इस मामले पर कार्रवाई का आश्वासन चीन के राष्ट्रपति से मिला। घुसपैठ के समाचारों के बीच चीन ने कैलाश-मानसरोवर क लिए नाथू ला से एक नया मार्ग खोलने का सहमति दी। इसके अलावा 20 बिलियिन डॉलर का निवेश, जनता से जनता के संपर्क,

संस्कृति, पर्यटन, कला पर जोर तथा महाराष्ट्र एवं गुजरात में चीनी औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा ग्वांगझाऊ-अहमदाबाद समझौते आदि इस यात्रा की मुख्य उपलब्धियां रहीं।

निष्कर्ष: भारत में जनता का भारी विश्वास अर्जित करने के साथ ही नरेन्द्र मोदी ने विश्व में भारत की पहचान को नए आयाम देने के प्रयास शुरू किए। उन्होंने न केवल दक्षेस को सभी सदस्य देशों से मिलकर मजबूत करने की कोशिश की बल्कि इसे इस क्षेत्र में गरीबी से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में प्रस्तुत किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षेस की साख तो बढ़ी ही साथ ही यह संवाद एवं सहयोग के मंच के रूप में स्थापित हुआ है। ब्रिक्स में यह कहकर कि 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' में सभी देश बराबर योगदान कर बराबर के साझेदार बने उन्होंने समानता पर अपने विश्वास को मूर्तरूप दिया है।

उन्होंने हर देश, भूटान या नेपाल, चीन या जापान, सबके साथ बराबरी, स्वाभिमान एवं सद्भाव के आधार पर संवाद स्थापित किया। वे जरूरत पड़ने पर कड़ाई से रखने में नहीं दिल के चाहे मामला चीन के साथ घुसपैठ का हो अथवा पाकिस्तान के द्वारा अलगाववादियों से बातचीत का। जहां भी नरेन्द्र मोदी जा रहे हैं लोग उनका भारी स्वागत कर रहे हैं और उनकी स्पष्टवादिता एवं गर्मजोशी से भारत की एक नई छवि उभर रही है।

विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के दबाव के सामने भारत का कड़ा रुख, आस्ट्रेलिया के साथ असैनिक परमाणु संधि पर हस्ताक्षर, इजरायल के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में मतदान, आतंकवाद पर कड़ा एवं बेबाक रूख, इराक में बंधकों को छुड़ाने में तत्परता एवं जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय कर एक उभरते हुए नए भारत की छवि नरेन्द्र मोदी ने गढ़ी है जो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त और अपनी बात रखने में बेबाक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर निर्णायक भूमिका निभाने को तत्पर है चाहे वह द्विपक्षीय मामला हो या बहुपक्षीय, किसी भी अवसर या स्थिति के लिए देश अब तैयार है। अब यह कहने में कोई शंका नहीं कि भारत में लोगों का दिल जीतने के बाद, नरेन्द्र मोदी अब पूरे विश्व का विश्वास जीत रहे हैं और इनके नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर उभर रहा है।■

पृष्ठ 22 का शेष...

दोनों लक्ष्यों में तालमेल बैठाया जा सकता है। गरीबों की सेवा करने के लिए अर्थ-व्यवस्था को अच्छा प्रदर्शन करना होना और हमें इतना अतिरिक्त उत्पादन करना होगा कि हम गरीबों में लाभ बाँट सकें। हम प्रत्येक भारतवासी को एक व्यापक सुरक्षा जाल देना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री जन धन योजना से यह सुनिश्चित होगा कि जनवरी 2015 तक लगभग हर घर में एक बैंक खाता होगा। इन बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़कर हम नरेगा, पेंशन भुगतान और एलपीजी सब्सिडियों जैसे लाभों का कुशलता से संवितरण कर पायेंगे।

हर गाँव-मुहल्ले में जनता के लिए सेवा केंद्र होंगे, जहां लोग कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के जरिये, हम गरीबी का नामो-निशान हटाने और हरेक भारतीय की मूलभूत आय सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे।

सीधे तौर पर कहा जाए तो हमारा आर्थिक दर्शन भारत की उत्पादक क्षमता को विश्व-प्रमुख स्तर तक लाने पर केन्द्रित है। हम सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, हकदारी में नहीं। हमारा ध्यान मुख्य रूप से अर्थ-व्यवस्था के आपूर्ति पक्ष पर है, ताकि हम कृषि संसाधन, सड़कें, पुल, बंदरगाह, पावर-प्लांट, कारखाने और सेवा केंद्र बना सकें, जिससे माल एवं सेवाओं का वितरण किफायती और प्रभावी ढंग से हो सके। साथ ही साथ, हमें अपनी युवा वर्कफोर्स को सक्षमता और निपुणता से लैस करना होगा, जिससे वे इन संस्थानों में काम करें और नवीन सुधार लायें।

हमें एक गहरी और सुचारू रूप से चलने वाली वित्तीय प्रणाली चाहिए जो आपूर्ति पक्ष के इस निर्माण-कार्य का वित्त-पोषण कर सके। और अंत में, हमें नियामक संस्थान, फुर्तीले नीति-निर्माता और तेजी से विकसित हो रहे विधान चाहिए, जिससे हम देश को सुशासन दे सकें। इस प्रकार हमारा आर्थिक दर्शन अन्य राजनैतिक दलों के खपत-उन्मुख, नासमझ लोकलुभावनवाद और मात्र हकदारी पर आधारित दर्शन से बिलकुल भिन्न है। ऐसी दलों और नीतियों के तकदीर में केवल विनाश है।

हमारे आर्थिक दर्शन से 'सबका विकास' उत्पन्न होता है। 1998 से 2004 तक अटल जी की सरकार ने इसका प्रदर्शन दिया था, और हम इस बार फिर यह साबित कर देंगे। ■

(लेखक लोकसभा सदस्य हैं)

विधानसभा चुनाव पर विशेष

हरियाणा में खिलेगा कमल

मिशन 60 प्लस का लक्ष्य

✍ संजीव कुमार सिन्हा

हरियाणा विधानसभा का चुनाव इस बार अभूतपूर्व होने वाला है। अब तक इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के बीच होता रहा है लेकिन इस बार पूरे राज्य में भाजपा अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है और वह चुनावी दौड़ में सबसे आगे चल रही है।

चुनाव मैदान में आठ दल हैं, इनमें कांग्रेस, भाजपा, बसपा, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, हजकां और इनेलो प्रमुख हैं। कुछ नए दल भी हैं। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री रहे गोपाल कांडा इस बार हरियाणा लोकहित पार्टी और कांग्रेस छोड़ चुके विनोद शर्मा जन चेतना पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं।

हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में शानदार प्रदर्शन किया। इस चुनाव में भाजपा का गठबंधन हजकां से था। हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा 8 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें उसने 7 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि हजकां 2 सीट पर लड़ी और दोनों सीटें हारीं। हजकां नेता कुलदीप बिश्नोई स्वयं सिरसा से हारे। इनेलो को दो और कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा। भाजपा-हजकां का साढ़े तीन साल पुराना गठबंधन अब टूट गया है।

गौरतलब है कि सन् 1966 में अस्तित्व में आने के बाद से हरियाणा विधानसभा के 11 चुनाव हो चुके हैं और राज्य में 3 बार राष्ट्रपति का शासन भी रहा है। वर्तमान विधानसभा का गठन 28 अक्तूबर 2009 को हुआ था। इसका कार्यकाल 27 अक्तूबर 2014 को समाप्त हो जाएगा।

हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 2009 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 40 सीटें, आईएनएलडी को 31, भाजपा को 4, हजकां को 6 और अन्य को 9 सीटें मिली थीं।

साल 2000 में भाजपा के 6 और 2005 में महज 2 विधायक थे।

भाजपा हरियाणा में सत्ता में आने को लेकर आश्वस्त है। उसने राज्य में मिशन 60 प्लस अभियान शुरू कर दिया है। विदित हो कि भाजपा इस बार अकेले ही सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा हरियाणा में सघन जन-जागरण अभियान चला रही है। पिछले महीने अगस्त में पार्टी ने चार रथयात्राएं निकालीं। गत 14 अगस्त को महेंद्रगढ़ में आयोजित विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने रवाना किया और भाजपा के चुनाव प्रचार का श्रीगणेश किया। श्री शाह ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से हरियाणा को भाजपायुक्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 31 अगस्त को चंडीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों में 'मिशन 60 प्लस' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा। हरियाणा प्रदेश भाजपा प्रभारी प्रो. जगदीश मुखी, प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री रामबिलास शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कांग्रेस सरकार पर कड़े प्रहार कर

15 अक्टूबर को होंगे चुनाव

चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। हरियाणा में एक चरण में चुनाव होगा। 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 19 अक्टूबर को मतगणना का काम किया जाएगा। 16244 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 27 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 1.62 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य में कुल मतदाताओं में 87,78,288 पुरुष और 74,81,851 महिलाएं हैं। राज्य की 90 सीटों में से 17 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं।

हरियाणा की जनता आज कांग्रेस शासन से त्रस्त हो चुकी है। अपने दस साल के शासन में प्रदेश की जनता की उपेक्षा और किसानों का शोषण करने के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए दिन झूठी घोषणाओं से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं पर अब जनता उनके किसी भी झांसे में आनेवाली नहीं है। हरियाणा में दस सालों में कांग्रेस सरकार के कुशासन, लोकसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन व भाजपा संगठन की उत्तरोत्तर प्रगति और मोदी सरकार के कामकाज के चलते इस बार प्रदेश में भाजपा अपने मिशन में कामयाब होती दिख रही है।

रही है और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर अभियान को गति प्रदान कर रही है।

राज्य में पिछले दो बार से यानी दस साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसकी हालत इस बार पतली है। कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। स्वाभाविकतया भाजपा संगठनात्मक रूप से हरियाणा में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। पार्टी के पक्ष में जबर्दस्त माहौल है। लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में शामिल हुए। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो अब केंद्रीय मंत्री हैं। पिछले दिनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद बीरेंद्र सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद से अब तक विभिन्न दलों के सैकंड़ों नेता भाजपा के साथ हो चुके हैं।

हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने पिछले दस सालों में राज्य को पीछे धकेल दिया। भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के चलते राज्य में अराजकता व्याप्त है। मुख्यमंत्री हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों में नियम-कानून को ताक पर रखा और करोड़ों की संपत्ति दिलाई। किसानों से कौड़ियों के दाम जमीन लेकर बिल्डरों और भू-माफियाओं को बड़े पैमाने पर भूमि दी गई। प्रदेश में पीने के पानी की दिक्कत है। गांव बदहाल है। शहरी मध्य वर्ग परेशान है। उद्योग धंधे चौपट हैं। युवाओं में बेकारी बढ़ रही है। शराबखोरी के चलते अपराध बढ़ रहे हैं। लैंगिक असमानता की चुनौती है। सरकारी नौकरियों, तबादलों तथा विकास कार्यों में भी भेदभाव हो रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की इनेलो की प्रदेश में बहुत ही खराब हालत है। एक तो वे स्वयं शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में हैं और दूसरे, उनके पुत्र अजय चौटाला भी जेल में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की 'हरियाणा जनहित कांग्रेस' भी मैदान में है जिसके नेता कुलदीप बिश्नोई हैं। 'बसपा' ने अब तक हरियाणा में लड़े पांच चुनावों में 4 बार एक-एक सीट प्राप्त की है।

हरियाणा की जनता आज कांग्रेस शासन से त्रस्त हो चुकी है। अपने दस साल के शासन में प्रदेश की जनता की उपेक्षा और किसानों का शोषण करने के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए दिन झूठी घोषणाओं से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं पर अब जनता उनके किसी भी झांसे में आनेवाली नहीं है। हरियाणा में दस सालों में कांग्रेस सरकार के कुशासन, लोकसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन व भाजपा संगठन की उत्तरोत्तर प्रगति और मोदी सरकार के कामकाज के चलते इस बार प्रदेश में भाजपा अपने मिशन में कामयाब होती दिख रही है। ■

दलों को मिला मत प्रतिशत

	2005		2009	
	lhVs	er ifr'kr	lhVs	er ifr'kr
dkaxzsl	67	42.5	40	35
buyks	9	26.8	31	25.8
funZyh;	10	13.7	7	13.2
gtdk	0	0.0	6	7.4
Hkktik	2	10.4	4	9.0
vU;	2	6.6	2	9.5

भारत-चीन सम्बन्ध और जिनपिंग का भारत दौरा

✍ विकास आनन्द

हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के तीन दिवसीय यात्रा पर थे। भारतीय मीडिया ने भारत चीन सीमा पर चली आ रही घुसपैठ की छिटपुट घटनाओं को सबसे महत्वपूर्ण खबर बनाने की कोशिश की। एक तरह से मीडिया 64 साल के विवाद को 64 घंटे में ही हल देखना चाहती थी। नेहरू की अदूरदर्शी नीति चाहे तिब्बत को लेकर हो या जम्मू-कश्मीर के प्रति उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। चीन तो हमारा पड़ोसी भी नहीं था। पंचशील समझौते के दौरान नेहरू ने तिब्बत पर औपचरिक रूप से चीन की संप्रुभता स्वीकार कर ली। और नहीं तो तिब्बत के याट्रंग एवं ग्यांग्तजी क्षेत्रों से भारतीय सेना तैनात करने का अधिकार छोड़ दिया और इस तरह चीन को हमने अपना सांस्कृतिक पड़ोसी से भौगोलिक पड़ोसी बना लिया।

64 सालों से चले आ रहे भारत-चीन सीमा विवाद को 64 घंटे में निपटारा तो नहीं किया जा सकता है। विवाद कब होता है? जब देशों के बीच अविश्वास कायम होता है। और विश्वास कायम बातचीत के बिना नहीं हो सकता। कम से कम चीन पाकिस्तान की तरह हमारे साथ आतंकवादी भेजकर छद्म युद्ध तो नहीं कर रहा है। निर्दोष नागरिकों की जान तो नहीं ले रहा है। फिर भी हम पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने की कोशिश करते हैं।

चीन के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान

भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए चीन के राष्ट्रपति सहमत हुए और अगले 5 वर्ष में अधिक संतुलित द्विपक्षीय व्यापार करने का निर्णय लिया गया। भारत के साथ व्यापार को संतुलित करने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने अपने देश का बाजार भारतीय उत्पादों, सेवायें तथा सूचना तकनीक के लिए खोलने की घोषणा की है। दोनों ही क्षेत्रों (सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी) में भारत का दबदबा है।

हुए द्विपक्षीय समझौते में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए सीमा विवाद और वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता का केन्द्र बिन्दु बनाया। भारत ने स्पष्ट कहा की बिना सीमा विवाद का भारत और चीन 21वीं सदी एशिया की शदी बनाने में मददगार साबित नहीं हो सकता। इसके पहले भारत-चीन द्विपक्षीय वार्ता में शायद ही सीमा विवाद और अतिक्रमण का मामला इस तरह से रखा गया था।

2011 में चीन के प्रीमियर वेन जीआबो भारत आए थे। उस समय की हमारी सरकार चीन के साथ व्यापार को संतुलित करने की दिशा में 2011 में चीन के प्रीमियर वेन जिआवो भारत आए थे और उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की सहमति हुई। लेकिन भारत के व्यापारिक घाटे को कम करके व्यापार को संतुलित करने की दिशा में कोई चर्चा नहीं हुई। 2011 की द्विपक्षीय कूटनीति का परिणाम जीरो सम गेम रहा। एक तरह से भारत के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया।

भारत-चीन व्यापार काफी असंतुलित है। बुरी तरह से चीन की तरफ झुका हुआ है। भारत-चीन के बीच कुल व्यापार 64 अरब डॉलर का है। चीन के साथ भारत का व्यापार असंतुलन बढ़कर 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसबार इस मुद्दे को भारत ने द्विपक्षीय वार्ता में उठाया। भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए चीन के राष्ट्रपति सहमत हुए और अगले 5 वर्ष में अधिक संतुलित द्विपक्षीय व्यापार करने का निर्णय लिया गया। भारत के साथ व्यापार को संतुलित करने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने अपने देश का बाजार भारतीय उत्पादों, सेवायें तथा सूचना तकनीक के लिए खोलने की घोषणा की है। दोनों ही क्षेत्रों (सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी) में भारत का दबदबा है।

दूसरी महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता कैलाश मानसरोवर के तीर्थ

यात्रियों के लिए चीन का सिक्किम में नाथू ला दर्रे से होकर जाने वाला रास्ता खोलने पर सहमत हो जाना है। मानसरोवर यात्रियों को चीन विशेष सुविधा मुहैया कराएगा तथा उत्तराखंड में मौजूदा लिपुलेख दर्रे से गुजरने वाली यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं में भी इजाफा करने पर सहमति हुई।

सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति का अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में जाकर बैठकर चरखा चलाना और कुछ समय व्यतीत करना है। इन सबके पीछे नरेन्द्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से गांधी के अहिंसा का संदेश विश्व की दूसरी बड़ी सैन्य शक्ति, जो हथियारों के रेस में अग्रणी देशों में है, को देने का प्रयास किया है।

राष्ट्रपति के तीन दिवसीय यात्रा के पहले ही दिन मीडिया में लद्दाख के चुमार क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन की खबर आई। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा द्विपक्षीय वार्ता में इस मुद्दे के उठाए जाने के बाद चीनी सेना को वापस जाना पड़ा। यहाँ तक कि चीनी राष्ट्रपति ने अपने देश जाकर चीनी सेना प्रमुख को बुलाकर डांट भी लगाई. चीन यह अच्छी तरह जनता है कि अमित्रतापूर्ण उसका रवैया भारत को अमेरिका और जापान के नजदीक ले जायेगा। यह परिणाम नरेन्द्र मोदी के मजबूत तथा दूरदर्शी नेतृत्व का परिचायक है।

इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। भारत को 1962 का युद्ध हारना पड़ा। क्योंकि उस समय देश में पंडित नेहरू के रूप में एक कमजोर और अदूरदर्शी नेतृत्व था। नरेन्द्र मोदी अच्छी तरह जानते है कि देश की प्राथिमिकता क्या है। नरेन्द्र मोदी भारत को सबसे पहले एक आर्थिक और सामरिक शक्ति बनाना चाहते हैं। इसे समृद्धितम देश बनाना चाहते हैं।

अमेरिका प्रथम विश्वयुद्ध से अलग रखा चूंकि उसकी प्राथमिकता उस समय अमेरिका को आर्थिक, समृद्धि और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाना था। दूसरे विश्वयुद्ध तक काफी मजबूत हो चुका था। और विश्व ने देखा किस तरह अप्रतिरोधनीय नाजी को चुनौती दी गई।

भारत का अभी का नेतृत्व छोटे-छोटे चीजों में उलझने के बजाए भारत को सब तरह से मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि मित्र बदल सकते है लेकिन पडोसी नहीं। अपने शपथ ग्रहण सामोरोह में पड़ोसियों को आमंत्रित करके नरेन्द्र मोदी ने यह सन्देश दे दिया कि भारत पड़ोसी से अच्छे सम्बंधों का पक्षधर है। इसमें दो मत नहीं है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व ने भारत का सम्मान विश्व में बढ़ाया है। यह ब्रिक सम्मेलन, प्रधानमंत्री का जपान दौरे से स्पष्ट होता है। ■

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में खाता खोला और असम में सीटों में वृद्धि की

हाल ही में 9 राज्यों में हुए 32 सीटों के विधान सभा तथा 3 सीटों पर लोकसभा के उपचुनावों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा के लिए यह एक अच्छी खबर है कि उसने पश्चिम बंगाल में अपना खाता खोला है और असम में सीटों में वृद्धि की है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में शुरूआत एक सदस्य के निर्वाचन से हुई है और दूसरी सीट पर वह दूसरे स्थान पर रही। भाजपा का मत प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। किन्तु उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर हुए उप चुनावों में से उसे केवल 3 सीटें ही मिल सकी और शेष 8 सीट समाजवादी पार्टी को मिलीं। समाजवादी पार्टी ने अकेली एक सीट पर हुए चुनाव में भी जीत हासिल की जो मुलायम सिंह के त्याग पत्र से रिक्त हुई थी। गुजरात में सभी 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, जिसमें से उसे छह सीटें मिली और साथ ही लोक सभा की वडोदरा सीट पर भी जीत हासिल की, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुई थी। कांग्रेस ने भाजपा से तीन सीटें छीन ली और उसका दावा है कि वह फिर से पुनर्जीवित हो रही है। सच्चाई इससे अलग हो सकती है। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस की चार सीटों में तीन सीटें गंवा दीं। देश के अन्य राज्यों में विपरीत रूख दिखाई पड़ा, भाजपा ने न केवल असम के उपचुनावों में वोट-शेयर का लाभ मिला, बल्कि वहां उसने अपने लिए एक सीट बढ़ा भी ली जिससे उसकी विधान सभा में संख्या कांग्रेस की कीमत पर छह तक पहुंच गई। चुनाव सिल्चर, लखीमपुर और जमुनामुख में भी हुए जिसके परिणाम आने पर भाजपा, कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने एक-एक सीट जीती। इनमें से भाजपा ने सिल्चर सीट कांग्रेस से छीनी, एआईयूडीएफ और कांग्रेस के पास एक-एक सीट बनी रही जो क्रमशः जमुनामुख और लखीमपुर से है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अकेली एक सीट पर हुए चुनाव में विजय प्राप्त की। ■

पटेल को जिम्मा दिया होता तो नहीं होती कश्मीर समस्या : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 17 सितंबर को कर्नाटक में बीदर के निकट गोर्ता गांव में एक शहीदी स्मारक तथा सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना के लिए आधारशिला रखे जाने के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित किया।

श्री शाह ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्म दिन (17 सितंबर) के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर में आई आपदा को संभालने में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना भी की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उपचुनावों के परिणाम भाजपा के लिए झटका नहीं हैं। श्री शाह ने कहा कि आलोचना करने वाले ये भूल रहे हैं कि भाजपा ने अपने धुर विरोधी राजनीतिक दलों को उनके गढ़ में हराकर असम और पश्चिम बंगाल में उपचुनावों में जीत दर्ज की है।

श्री शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उन्हें कल घोषित हुए परिणामों से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अब उन्हें महाराष्ट्र तथा हरियाणा सहित चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर ध्यान देना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों को भाजपा के विजय अभियान पर संशय है, उन्हें वह बताना चाहते हैं कि पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज करेगी और दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा के विजय अभियान को कोई नहीं बदल सकता। भाजपा इन राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

श्री शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा सरकार ने कई अहम फैसले करके लोगों का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत तीन करोड़ से अधिक लोगों के अब तक बैंक खाते खुल चुके हैं। इन्हें बीमा सुविधा भी दी गई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का भारत में विलय का कार्य सरदार बल्लभभाई पटेल को सौंपा गया होता तो न कश्मीर की समस्या पैदा होती और न ही भारत ने पाकिस्तान को अवैध रूप से राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा करने दिया होता। श्री शाह देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को कश्मीर मुद्दा अनसुलझा छोड़ देने के लिए कठघरे में भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 300 रजवाडों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किए और सफलता पाई। अगर उन्हें जम्मूकश्मीर के मुद्दे में भी शामिल किया गया होता तो आज कश्मीर की समस्या सामने नहीं होती और पूरा राज्य देश का एक अभिन्न अंग होता।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का भारत में विलय का कार्य सरदार बल्लभभाई पटेल को सौंपा गया होता तो न कश्मीर की समस्या पैदा होती और न ही भारत ने पाकिस्तान को अवैध रूप से राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा करने दिया होता। श्री शाह देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को कश्मीर मुद्दा अनसुलझा छोड़ देने के लिए कठघरे में भी खड़ा किया।

श्री शाह ने कहा कि देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस तरह की थी कि उनके बाद उनका कोई भी परिजन राजनीति में नहीं आया। कोई नहीं जानता कि अभी वे लोग क्या कर रहे हैं। ■